

[2023] 7 एस. सी. आर. 476

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस

वी.

राजेश अग्रवाल और ओआरएस

(2022 की सिविल अपील संख्या 7300)

27 मार्च, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और

हिमा कोहली, जे।]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग)

वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा) निर्देश 2016-धोखाधड़ी पर प्रमुख निर्देश-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-ऑडी अल्टरम पार्टम का नियम-नागरिक अपील भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसके द्वारा रिपोर्ट करना) को चुनौती देने से उत्पन्न होती है।

वाणिज्यिक बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थान) निर्देश 2016-ये

विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष निर्देशों को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उधारकर्ताओं को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई के किसी भी अवसर की परिकल्पना नहीं की गई है-क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए-आयोजित किया गया: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसे फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में उनके खाते को वर्गीकृत करने से पहले रिपोर्ट करें, और बैंकों/जेएलएफ द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए

इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए; और चूंकि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश स्पष्ट रूप से एक अवसर प्रदान नहीं करते हैं

अपने खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ताओं को सुनना, ऑडी अल्टरम पार्टम को इसके प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए

उन्हें मनमानेपन की बुराई से बचाने के निर्देश।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग)

वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ. एल. एस. द्वारा) निर्देश 2016-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-उधारकर्ताओं के लिए नागरिक परिणाम चाहे

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से नागरिक परिणाम सामने आते हैं -

उधारकर्ता-आयोजित: धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों का खंड 8.12

476 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस

खंड 8.12 उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपायों से संबंधित है। 1

यह प्रावधान है कि जानबूझकर चूक करने वालों के लिए लागू दंडात्मक प्रावधान धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू होंगे, जिनमें प्रवर्तक और

ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक-इसके अलावा, ऋणकर्ता धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत निम्नलिखित परिणाम भुगतने के लिए भी उत्तरदायी हैं: क) आर. एफ. ए. या धोखाधड़ी खातों (खंड 8.12.2) के मामले में कोई पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है; ख) धोखाधड़ी वाले उधारकर्ता से जुड़े निपटान पर कोई समझौता करने की अनुमति नहीं है जब तक कि

शर्तों में कहा गया है कि आपराधिक शिकायत जारी रखी जाएगी

(खंड 8.12.3)-धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है।

उधारकर्ता के लिए परिणाम-धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में उधारकर्ता के खाते का वर्गीकरण वस्तुतः उधारकर्ता के लिए क्रेडिट फ्रीज की ओर ले जाता है, जिसे वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजारों से वित्त जुटाने से प्रतिबंधित किया जाता है -

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन के अलावा ऋणकर्ता के लिए वित्त जुटाना घातक हो सकता है जिससे उसकी 'नागरिक मृत्यु' हो सकती है-क्योंकि, किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराना या अपने अधिकारों और/या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से, यह प्राथमिक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए।

और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई की मांग की गई है

सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग)

वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ. एल. एस. द्वारा) निर्देश 2016-ऑडी अल्टरम पार्टिम का कोई निहित बहिष्करण नहीं-आर. बी. आई. और ऋणदाता बैंकों ने तर्क दिया है कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश निहित रूप से हैं।

सुनवाई के अधिकार को बाहर करें-आयोजित: धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट रूप से उधारकर्ताओं को उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कार्रवाई करने से पहले सुनने के अधिकार को बाहर नहीं करते हैं-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक कानून या एक अधिसूचना में पढ़ा जा सकता है जहां यह एक पक्ष को सुनवाई का अवसर देने पर चुप है जिसके अधिकार और हित पारित किए जाने वाले आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है।

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय के दो बुनियादी सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र में निहित हैं: (i) कोसा सुआ में निमो जुडेक्स, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के मामले में

न्यायाधीश नहीं होना चाहिए; और (ii) ऑडी अल्टरम पार्टेम, जिसका अर्थ है कि प्रशासनिक से प्रभावित व्यक्ति, [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय लेने से पहले न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्रवाई की सुनवाई की जानी चाहिए। अदालतें आम तौर पर किसी वैधानिक प्रक्रिया की व्याख्या का समर्थन करती हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रावधान क्योंकि यह माना जाता है कि वैधानिक प्राधिकरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: ऑडी अल्टेरम पार्टेम

1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत केवल कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं। वे महत्वपूर्ण दायित्वों का गठन करते हैं जिनका निर्णय लेने और निर्णय लेने वाले अधिकारियों द्वारा पालन करने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया और सार दोनों के संदर्भ में मनमाना कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं। दो बुनियादी बातें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भारत में निहित हैं।

न्यायशास्त्र: ((i) कार्यकारण में न्यायनिर्णायक पद, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए; और (ii) कार्यनिर्णायक पद, जिसका अर्थ है कि प्रशासनिक, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले सुना जाना चाहिए। अदालतें आम तौर पर एक वैधानिक की व्याख्या का समर्थन करती हैं।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उक्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, व्यक्त भाषा और कानून की मूल योजना पर निर्भर करता है जिसके तहत प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रकृति और उद्देश्य जिसके लिए शक्ति प्रदान की जाती है, और अभ्यास का अंतिम प्रभाव

उस शक्ति से। [पैरा 29] [502-ई-जी]

के खिलाफ आपराधिक शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए एक राय उधारकर्ता। उक्त अध्याय के तहत, ऋणदाता बैंकों को उधारकर्ता के ऋणों को वर्गीकृत करने के बाद किसी उधारकर्ता को सी. बी. आई. को रिपोर्ट करना होता है।

धोखाधड़ी के रूप में खाता। हालांकि, का वर्गीकरण

प्रवर्तन अधिकारियों के साथ आपराधिक शिकायत; इसमें खंड के तहत निर्धारित उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक परिणाम भी शामिल हैं। 8.12 . स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस V के तहत एक सूचित राय बनाने की प्रक्रिया।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। आर. बी. आई. और ऋणदाता बैंकों ने भी अपनी लिखित दलीलों में इसे स्वीकार किया है। अब यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि ऑडी अल्टरम पार्टम का नियम न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के अलावा प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होता है। प्रशासनिक कानून में यह भी एक तय स्थिति है कि इसके लिए प्रावधान करना अनिवार्य है

जब कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो सुनवाई का अवसर किसी व्यक्ति या संस्था के लिए नागरिक परिणामों में। [पैरा 31,32] [503-डी

जी]

3. भारतीय रिज़र्व बैंक और ऋणदाता बैंकों ने तर्क दिया है कि नागरिक परिणामों पर खंड 8.12 में विचार किया गया है। 1 मास्टर की

धोखाधड़ी पर निर्देश उचित हैं। उक्त खंड के तहत, कंपनी के प्रवर्तकों और निदेशकों सहित उधारकर्ता,

वित्तीय बाजारों और ऋण बाजारों से पांच साल की अवधि के लिए और संभवतः उससे आगे भी ऋण प्राप्त करने पर रोक है।

आर. बी. आई. और ऋणदाता बैंकों के अनुसार, इस तरह के प्रतिबंध को जनहित के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जबकि

यह स्वीकार करते हुए कि जिस प्रक्रिया में निर्धारित किया गया है

धोखाधड़ी पर प्रमुख निर्देशों की परिकल्पना जनहित में की गई है, बैंकिंग प्रणाली की रक्षा के लिए, उधारकर्ताओं को होने वाले गंभीर नागरिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा

38] [505 - जी; 506-ए-बी]

4. धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से वस्तुतः उधारकर्ता के लिए क्रेडिट फ्रीज हो जाता है, जिसे वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजारों से वित्त जुटाने से रोक दिया जाता है। उठाने से बार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन के अलावा ऋणकर्ता के लिए वित्तीय स्थिति घातक हो सकती है जिससे उसकी 'नागरिक मृत्यु' हो सकती है। चूंकि प्रतिबंध किसी व्यक्ति या संस्था को अपने अधिकारों और/या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से वंचित करता है, इसलिए यह प्राथमिक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई की मांग की जाती है।

सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, रोक लगाना किसी उधारकर्ता को ऋण लेने से रोकने के समान है। [पैरा 42] [509 - ए-सी]

ऑडी अल्टरम पार्टम का कोई निहित बहिष्करण नहीं

5. धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं हैं

वर्ग [2023] 7 एस. सी. आर. की कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को सुनने के अधिकार को बाहर करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखाधड़ी के रूप में उनका खाता शुरू किया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक कानून या एक अधिसूचना में पढ़ा जा सकता है जहां यह एक पक्ष को सुनवाई का अवसर देने पर चुप है जिसके अधिकार और हित पारित किए जाने वाले आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है। [पैरा 53] [513-ई]

6. इसलिए, ऑडी अल्टरम पार्टिम का तात्पर्य है कि एक इकाई जिसके खिलाफ साक्ष्य एकत्र किया जाता है, उसे: (i) एक प्रदान किया जाए

फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उधारकर्ता की भागीदारी प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय में ऋणदाता बैंकों द्वारा तथ्यों और कानून के प्रति विवेक का उचित अनुप्रयोग शामिल है। ऋणदाता बैंक, या तो व्यक्तिगत रूप से या जेएलएफ के माध्यम से, यह तय करना होगा कि क्या किसी उधारकर्ता ने ऋण समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, और इस तरह के निर्धारण के आधार पर ऋणदाता बैंक उचित उपचार की तलाश कर सकते हैं। इसलिए,

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, और धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। [पैरा 65] [520-एफ-एच]

7. निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: आई. एफ. आई. आर. दर्ज करने और दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की आवश्यकता नहीं है। धोखाधड़ी के रूप में खाते के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप न केवल जांच एजेंसियों को अपराध की सूचना दी जाती है, बल्कि उधारकर्ताओं के खिलाफ अन्य दंडात्मक और नागरिक परिणाम भी होते हैं। खंड 8.12 के तहत उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त तक पहुँच से वंचित करना। 1 धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के लिए गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं; iv. खंड 8.12 के तहत ऐसा प्रतिबंध। 1 धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों का होना उधारकर्ताओं को काली सूची में डालने के समान है

बैंकों द्वारा ऋण के लिए अविश्वसनीय और अयोग्य। इस न्यायालय ने लगातार कहा है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

ऑडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस का आवेदन V. राजेश अग्रवाल और ओआरएस

धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत अल्टराम पार्ट्स को निहित रूप से बाहर नहीं किया जा सकता है। विचार की गई समय सीमा को देखते हुए धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के साथ-साथ अपनाई गई प्रक्रिया की प्रकृति के तहत, ऋणदाता बैंकों के लिए यह उचित रूप से व्यावहारिक है कि वे अपने खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करें। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें निष्कर्षों की व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, और धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में उनके खाते को वर्गीकृत करने से पहले बैंकों/जेएलएफ द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए; और चूंकि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट रूप से उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हैं उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले, उन्हें मनमानेपन के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए निर्देशों के प्रावधानों को पढ़ना होगा। [पैरा 81] [528-ए-एच]

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एस. सी. आर. 621; भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398: [1985] 2 पूरक। एससीआर 131; ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम (1985) 3 एस. सी. सी. 545 [1985] 2 पूरक। एससीआर 51; सी बी गौतम बनाम। भारत संघ (1993) 1 एससीसी 78: [1992] 3 पूरक। इसके बाद एस. सी. आर. 12 आया।

उडीसा राज्य बनाम। डॉ. (सुश्री) बिनापानी देई ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1269 [1967] एस. सी. आर. 625; केनरा बैंक बनाम। वी. के. अवस्थी

(2005) 6 एससीसी 321 [2005] 3 एससीआर 81; एरसियन

उपकरण और रसायन लिमिटेड V. पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 1 एससीसी 70 [1975] 2 एससीआर 674; जोसेफ विलिंगंदन बनाम। कार्यकारी अभियंता (1978) 3 एस. सी. सी. 36: [1978] 3 एस. सी. आर. 514; रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य (1989) 1 एससीसी 229: [1988] 3 पूरक। एससीआर 867; गोरखा सुरक्षा सेवा बनाम। सरकार (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2014) 9 एस. सी. सी. 105: [2014] 13 एस. सी. आर. 617; महाराष्ट्र राज्य बनाम पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट (2007) 3 एस. सी. सी. 587:

[2007] 1 एससीआर 87; स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम।

का संघ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत (1981) 1 एससीसी 664: [1981] 2 एससीआर 533; मंगीलाल वी. मध्य प्रदेश राज्य (2004) 2 एससीसी 447: [2004] 1 एस. सी. आर. 1; के आई शेफर्ड बनाम। भारत संघ (1987) 4 एससीसी 431: [1988] 1 एस. सी. आर. 188; भारत संघ बनाम कर्नल जे एन सिन्हा (1970) 2 एस. सी. सी. 458: [1971] 1 एससीआर 791; केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 13 एससीसी 733: [2011] 9 एस. सी. आर. 19-पर निर्भर।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम जाह डेवलपर्स (2019) 6 एससीसी 787: [2019] 7 एस. सी. आर. 701; भारत संघ बनाम। कर्नल जे एन सिन्हा (1970) 2 एस. सी. सी. 458: [1971] 1 एससीआर 791; अंजू चौधरी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 6 एससीसी 384: [2012] 13 एस. सी. आर. 901; ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ (1969) 2 एस. सी. सी. 262 [1970] 1 एस. सी. आर. 457; शासी निकाय, सेंट एंथोनी कॉलेज, शिलांग और अन्य बनाम। रेव. फा. पॉल शिलांग का पेट्टा (1988) पूरक एस. सी. सी. 676: [1988] पूरक। एससीआर 507; उमा नाथ पांडे और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एससीसी 40: [2009] 4 एस. सी. आर. 374; मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2 एससीआर 272; डी. के. यादव बनाम। जे एम ए इंडस्ट्रीज (1993) 3 एस. सी. सी. 259: [1993] 3 एस. सी. आर. 930; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट

कं. लिमिटेड बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एस. सी. आर. 406; जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1371: [1962] पूरक। एस. सी. आर. 632; इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक (2020) 10 एससीसी 274: [2020] 2 एससीआर 297; अजीत कुमार नाग बनाम। महाप्रबंधक (पी. जे.), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड (2005) 7 एससीसी 764: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 314; केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1973) 1 एससीसी 380: [1973] 3 एससीआर 22; दिल्ली क्लॉथ मिल्स एंड जनरल मिल्स बनाम। भारत संघ (1983) 4 एससीसी 166: [1983] 3 एस. सी. आर. 438; ई. पी. रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य (1974) 4 एससीसी 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 328; ए. पी. राज्य बनाम। मैकडॉवेल (1996) 3 एससीसी 709: [1996] 3 एससीआर 721; ओम कुमार बनाम। भारत संघ (2001) 2 एससीसी 386: [2000]

4 पूरक। एस. सी. आर. 693; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम। पी सी कक्कड़ (2003) 4 एस. सी. सी. 364 [2003] 1 एस. सी. आर. 1034; छावनी बोर्ड बनाम।

तारामणि देवी 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 501; दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस

निगम बनाम। डीटीसी मजदूर कांग्रेस 1991 सप्लीमेंट (1)

एससीसी 600: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 142; सहारा इंडिया

(फर्म), लखनऊ बनाम। आयकर आयुक्त,
सेंट्रल-1 (2008) 14 एस. सी. सी. 151: [2008] 6 एससीआर 427;

क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान

(2010) 9 एससीसी 496: [2010] 10 एससीआर 1070-संदर्भित

को।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 5 वां संस्करण (1979); पी रामनाथ

अय्यर, 'द लॉ लेक्सिकॉन: विश्वकोश कानून

शब्दकोश '(1997 ई. डी. एन.)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 7 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1971] 1 एससीआर 791

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

[2012] 13 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[1970] 1 एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1988] पूरक। एससीआर 507

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2009] 4 एससीआर 374

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

[1967] एससीआर 625

पैरा 33

उस पर भरोसा करें

[1978] 2 एससीआर 621

पीछा किया।

पैरा 34

[1978] 2 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[1993] 3 एससीआर 930

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2005] 3 एससीआर 81

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

[1975] 2 एससीआर 674

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

[1978] 3 एससीआर 514

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[1988] 3 पूरक। एससीआर 867

उस पर भरोसा करें

पैरा 46

[2014] 13 एससीआर 617

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[2007] 1 एससीआर 87

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

[1992] 1 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[1962] पूरक। एससीआर 632

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[2020] 2 एससीआर 297

संदर्भित किया गया है

50 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 एससीआर 533

उस पर भरोसा करें

पैरा 54

[1981]

[2004] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 56

[2005] 3 पूरक। एससीआर 314

संदर्भित किया गया है

पैरा 57

[1985] 2 पूरक। एससीआर 131

पीछा किया।

पैरा 57

[1988] 1 एससीआर 188

उस पर भरोसा करें

पैरा 59

[1973] 3 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 62

[1983] 3 एससीआर 438

संदर्भित किया गया है

पैरा 66

[1974] 2 एससीआर 348

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

[1996] 3 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

[2000] 4 पूरक। एससीआर 693

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

[2003] 1 एससीआर 1034

पैरा 68

संदर्भित किया गया है

1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 501

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 142

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[1985] 2 पूरक। एससीआर 51

पीछा किया।

पैरा 72

[1971] 1 एससीआर 791

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[1992] 3 पूरक। एससीआर 12

पैरा 74

पीछा किया।

[2008] 6 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पैरा 75

[2011] 9 एस. सी. आर 19

उस पर भरोसा करें

पैरा 76

[2010] 10 एससीआर 1070

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णय: सिविल अपील

2022 का सं. 7300।

उच्च न्यायालय के 10.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 19102 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए।

के साथ

सिविल

अपील सं। 7301 , 7302 , 7303 , 7304 , 7305 , 7306 , 7307

2022 और रिट याचिका सं। 138 2022 तक।

तुषार मेहता, एसजी, गोपाल जैन, रंजीत कुमार, ध्रुव मेहता, डी।

अभिषेक मनु सिंघवी, नवीन पाहवा, अरुणाभ चौधरी, गोपाल जय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस

श्री एड. , संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, सुश्री अक्षता जोशी, सुश्री शुभा कपूर, सुश्री प्रज्ञा बघेल, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री निशा शर्मा, सुश्री जागृति भारती, महेश अग्रवाल, सुमेश धवन, ऋषि अग्रवाल, वस्तला काक, हिमांशु सतीजा, प्राणजीत भट्टाचार्य, कैलाशनाथ, वी. मुरली मनोहर, निशांत

राव, ई. सी. अग्रवाल, सूरज प्रकाश, मृणाल लिटोरिया, सुश्री प्रियंका सोलंकी, सुश्री निधि मोहन पराशर, रवि पाहवा, सुश्री मोनिशा हांडा, राजुल श्रीवास्तव, मोहित डी. राम, अनुभव शर्मा, कानू अग्रवाल, सुश्री नीला केदार गोखले, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री प्रवीणा गौतम, अरविंद कुमार शर्मा, एम. के. मरोरिया, मयंक पांडे, अन्नम

वेंकटेश, सुश्री सैरिका राजू, सुश्री स्वाति घिलिडयाल, जसमीत सिंह, महिंदर सिंह हूरा, सैफ अली, दिवजोत सिंह भाटिया, पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया, सुश्री रुषित सलूजा, सुश्री मंदीप कौर, सिद्धार्थ हांडा, कर्मा दोरजी, डेचेन डब्ल्यू. लाचुंगपा, अनिरुद्ध एम. सेठी, सिद्धार्थ सीम, सौरभ टंडन, सुश्री ऋचा कपूर, कुणाल आनंद, सुश्री शिवानी शर्मा, सुश्री ज्योति जोंगलूजू, मैसर्स। कोच, सुश्री सुवर्णा कश्यप, पंकज विवेक, कृष्ण कुमार, नितिन पाल, स्वकीर्तिमाला दुबे, आनंद शंकर झा, अर्पित गुप्ता, सुश्री मीनाक्षी एस. देवगन, गिरीश भारद्वाज, अभिलेख तिवारी, आलोक कुमार, जी. एन. रेड्डी, मनन गंभीर, सुश्री गरिमा सोनी, सुश्री नीतू राही, राहिल पंडित, ए. राधाकृष्णन, सुश्री आस्था दीप, सुश्री रूमा सरसानी, पी. बी. ए. श्रीनिवासन, पार्थ टंडन, सुश्री प्रेरणा सभरवाल, सुश्री सृष्टि बंसल, कुमार, वी. अरविंद, अमित के. नैन, वृजेश कुमार टैम्बर, येसु रुस्तगी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

ए. पृष्ठभूमि।

..... 4 *

बी.

तथ्या।

... 5 *

.....10 *

ग. प्रस्तुतियाँ।

..... 15 *

डी. विश्लेषण।

डी. 1 विनियामक ढांचा

... 15 *

डी. 2 ऑडी अल्टरम पार्टम।

..... 25 *

... ..

डी. 3

ऑडी अल्टरम पार्टम का कोई निहित बहिष्करण नहीं

..39 *

... 48 *

डी. 4

संवैधानिक वैधता को चुनौती

निष्कर्ष।

..... 57 *

ई.

* एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. पृष्ठभूमि

1. दीवानी अपील भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) के लिए एक चुनौती से उत्पन्न होती है और

एफ. आई.) निर्देश 2016 चुनें। 1 भारतीय रिजर्व बैंक 2 द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उधारकर्ताओं के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उनकी सुनवाई का कोई अवसर नहीं है। का उच्च न्यायालय

तेलंगाना ने विवादित फैसले में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। आर. बी. आई. और ऋणदाता बैंकों ने इन दीवानी अपीलों के माध्यम से इस निर्णय पर हमला किया है।

2. इस पृष्ठभूमि में न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को इसके प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश। पालन करने के कारणों के लिए, हमारा मानना ​​है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विशेष रूप से ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम को धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों में अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसे मनमानेपन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। चूंकि किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ता के लिए गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, इसलिए निर्देशों को उनमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को पढ़कर उचित रूप से समझा जाना चाहिए।

B. तथ्य

आई. 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 3931; 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4922; 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 5056 3. बी. एस. लिमिटेड एक कंपनी है जो बिजली संचरण और वितरण, निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा और खनिज संसाधनों के व्यवसाय में लगी हुई है। इसने एक करोड़ रुपये का ऋण लिया। 1406 विभिन्न बैंकों से रु. कंपनी अपने भुगतान को पूरा करने में विफल रही

1 " धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश "2" भारतीय रिजर्व बैंक "

3 2019 की रिट याचिका संख्या 19102 4 "जेएलएफ"

5 " एन. पी. ए. "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम. राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना योजना और एक सुझाव दिया

11 जुलाई 2016 को आयोजित अपनी बैठक में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी अध्ययन। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, जेएलएफ ने यह कहते हुए इस मुद्दे को बंद कर दिया कि कोई अनियमितता नहीं थी। हालांकि, टी. ई. वी. अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि कंपनी एस 4 ए योजना के लिए पात्र नहीं थी और उसने इसे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

अपने खाते को नियमित करने के लिए बैंकलपिक योजना। इस बीच, आईडीबीआई बैंक-ऋणदाता बैंकों में से एक-ने कंपनी के खाते को हरी झंडी दिखाई।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत भी कार्यवाही शुरू की गई थी। 15 फरवरी 2019 को, जे. एल. एफ. ने खंड 2.2 का आह्वान करके कंपनी के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। 1 (छ) धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश। इसके बाद, धोखाधड़ी पहचान समितियों ने 31 जुलाई 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कंपनी के खाते को धोखाधड़ी के रूप में पहचाना गया। कंपनी ने 15 फरवरी 2019 के जेएलएफ के फैसले और 31 जुलाई 2019 के एफ. आई. सी. के प्रस्ताव दोनों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

तेलंगाना।

5. 10 दिसंबर 2020 के एक फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने रिट याचिका को यह मानते हुए अनुमति दी कि

ऑडी अल्टरम पार्टम को खंड 8.9 में पढ़ा जाना चाहिए। 4 और 8.9। 5 धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश। उच्च न्यायालय ने ऋणदाता बैंकों को आगे निर्देश दिया: (i) फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने के बाद उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना; और (ii) अपने खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना। उच्च न्यायालय के फैसले को 2021 के एसएलपी (सी) संख्या 3931 में चुनौती दी गई थी। 15 अप्रैल 2021 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित शर्तों में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी:

" इस बीच, संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक द्वारा पारित कार्यवृत्त/आदेश दिनांक 15.02.2019 पर कार्रवाई नहीं की जानी है। जहाँ तक उच्च न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।

II. 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 762; 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 873; और 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 1514

6. अपीलार्थी एक कंपनी है जो इसके निर्माण में शामिल है

तेलंगाना राज्य में खाद्य तेल, वसा, चावल और साबूदाना उत्पाद।

6 " एस 4 ए योजना "

7 " टी. ई. वी. "

एफ. आई. सी. "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2003 से 2015 तक, अपीलार्थी ने 500 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। 675 आंध्र बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय) के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ से रु। अपीलार्थी को 31 मार्च 2018 से 14 मई 2018 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। इसके बाद, ऋणदाताओं के संघ ने जेएलएफ की एक बैठक में 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए अपीलार्थी का फॉरेंसिक ऑडिट करने का निर्णय लिया। द.

अपीलार्थी ने लेखापरीक्षा प्रक्रिया में भाग लिया और सभी जानकारी प्रस्तुत की

समय-समय पर लेखा परीक्षक द्वारा आवश्यक। सितंबर 2019 में, अपीलार्थी को पता चला कि उसके खाते को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती आंध्र बैंक) द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया है। उस वर्गीकरण से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों से निपटने से इनकार कर दिया कि वे 2021 के एसएलपी (सी) संख्या 3931 में इस न्यायालय के समक्ष लंबित थे। 22 तारीख के अपने फैसले के अनुसार

दिसंबर 2021 में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि अपीलार्थी के खाते को धोखाधड़ी के रूप में उचित रूप से वर्गीकृत किया गया था क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष थे।

7. 24 जनवरी 2022 को, इस न्यायालय ने 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 762 में नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि मामले की सूचना आयोग को नहीं दी जा सकती है।

अभी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो। 28 मार्च 2022 को, इस न्यायालय ने 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 873 और 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 1514 में एक समान विज्ञापन-अंतरिम आदेश पारित किया।

III. 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 2980

8. अपीलार्थी गोल्डन जुबली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रवर्तक और निदेशक है। 10 जी. जे. एच. पी. एल. ने प्रत्यर्थी बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त की।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर 3 मई 2019 को अपीलार्थी के खाते को लाल झंडी दिखाई। अपीलार्थी के खाते को 14 अगस्त 2019 को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सीबीआई में एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई थी। अपीलार्थी को 2021 में धोखाधड़ी के रूप में अपने खाते के वर्गीकरण के बारे में पता चला। 9 "

सीबीआई "

10 " जीजेएचपीएल "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम. राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

जब उन्हें एफ. आई. आर. की एक प्रति मिली। अपीलार्थी ने धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों की वैधता को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2021 के अपने फैसले में कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के मुद्दे पर अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 3931 इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में प्रतिकूल निष्कर्षों को देखते हुए अपीलार्थी के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

IV. 2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 138 और एसएलपी (सी) संख्या 3388

2022 का 9. अपीलार्थी मेसर्स विमल ऑयल एंड फूड्स लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशकों में से एक है। उक्त कंपनी ने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया

एक समय अवधि में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से। 2015 में, प्रत्यर्थी बैंक के लेखा परीक्षक ने कंपनी के खातों में कुछ अनियमितताओं को चिह्नित किया। एक विशेष लेखा परीक्षा के आधार पर, प्रतिवादी बैंक ने 30 सितंबर 2015 को कंपनी के खाते को एन. पी. ए. घोषित किया। इसके बाद 05 जुलाई 2016 को कंपनी के खाते को लाल झंडी दिखाई गई।

उत्तरदाता बैंक। इस बीच, 19 दिसंबर 2017 को कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई और अपीलार्थी को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में निलंबित कर दिया गया। निलंबन पर, अपीलार्थी को बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था

जेएलएफ। अपीलार्थी को कथित तौर पर पता चला कि प्रतिवादी बैंक ने 21 फरवरी 2018 को बिना किसी सूचना के उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी बैंक द्वारा सीबीआई को संबोधित एक पत्र के आधार पर, अपीलार्थी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। अपीलार्थी का आरोप है कि उन्हें अपने खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने और प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में जानकारी तभी मिली जब प्राथमिकी के अनुसरण में उनके आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी बैंक की कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए एक विशेष नागरिक आवेदन दायर किया, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने 23 दिसंबर 2021 के अपने फैसले द्वारा लेटर पेटेंट अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी, जिसमें अपीलार्थी को प्रतिवादी बैंक को एक अभ्यावेदन को संबोधित करने की अनुमति दी गई, लेकिन व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों की वैधता को चुनौती देकर इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का भी आह्वान किया है।

आर. पी. "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग. प्रस्तुतियाँ

10. उधारकर्ताओं की ओर से हमने डॉ. अभिषेक मनु पंचम, श्री रंजीत कुमार, श्री ध्रुव मेहता, श्री अरुणाभ चौधरी, अविन पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और श्री सूरज प्रकाश, विद्वानों को सुना है। वकील का कहना है कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में एन. टी. के वर्गीकरण की प्रक्रिया इससे ग्रस्त है क्योंकि:

खंड 8.9 के तहत 4 और 8.9। 5 मास्टर दिशाओं पर

ए।

धोखाधड़ी, उधार लेने वाली कंपनी या उसके प्रवर्तकों और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। उन्हें बचाव पेश करने का अवसर नहीं दिया जाता है और यहां तक कि उन्हें अंतिम निर्णय की एक प्रति भी प्रदान नहीं की जाती है।

बी।

ऋणकर्ता के बैंक खातों का धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण

धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं। के खंड 8.12 के तहत दंडात्मक प्रावधान

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश प्रवर्तकों, निदेशकों और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों पर भी लागू होते हैं। एक बार

धोखाधड़ी जैसे कि सी. बी. आई. में शिकायत दर्ज करना और प्रवर्तकों और निदेशकों को संस्थागत वित्त तक पहुँचने से रोकना। इसके अलावा, किसी खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई कलंकित है, जो उधारकर्ता को काली सूची में डालने के समान है, जो ऋण लेने के उनके अधिकार को प्रभावित करता है। प्रतिष्ठा . इस प्रकार, संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप

धोखाधड़ी के रूप में खाते का वर्गीकरण। धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं

सी.

14 , 19 , और भारत के संविधान के 21 के रूप में वे एक कंपनी और उसके प्रवर्तकों और निदेशकों को पहुँचने से रोकते हैं

पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय और ऋण बाजार बिना कारण बताए नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान किए।

डी।

व्यक्तिगत सुनवाई के अलावा। द मास्टर
धोखाधड़ी पर निर्देश ऑडी अल्टरम पक्ष के अन्य पहलुओं पर अच्छा नहीं है जैसे कि भारत के एनके और
ओआरएस बनाम पर लगाए गए आरोपों की सूचना।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई]

और एकत्र किए गए साक्ष्य, प्रस्तावित दंड की सूचना, अन्य के बीच। धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक कंपनी या उसके प्रवर्तक

और निदेशकों को यह भी सूचित नहीं किया जाता है कि उन्हें धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जुर्माना लगाया गया है

उन पर।

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश इस बात पर चुप हैं कि क्या उधारकर्ता फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद और यह तय करने से पहले कि क्या उधारकर्ता के खाते को वर्गीकृत किया जाना चाहिए, सुनवाई के अवसर का हकदार है या नहीं।

धोखाधड़ी। चूंकि खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय के महत्वपूर्ण नागरिक परिणाम होते हैं, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों में पढ़ा जाना चाहिए।

खंड 8.12। 5 धोखाधड़ी पर प्रमुख निर्देशों का स्पष्ट रूप से

यह निर्धारित करता है कि तीसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। निर्देश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं क्योंकि एक तरफ वे तीसरे पक्ष को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उधारकर्ताओं को इस तरह के अवसर से वंचित कर दिया जाता है।

हालांकि मास्टर निर्देशों का उद्देश्य और उद्देश्य

धोखाधड़ी पर तेजी से पता लगाना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना है, ऐसी आवश्यकताएं प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों की प्रयोज्यता को बाहर करने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकती हैं।

न्याय।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जाह डेवलपर्स 1 2 12 ने प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता में पढ़ा

उधारकर्ता को विलफुल घोषित करने के उद्देश्यों के लिए

चूककर्ता। जाह डेवलपर्स में निर्धारित सिद्धांत

(उपर्युक्त) वर्तमान मामलों पर पूरी तरह से लागू होगा।

तैयारी के दौरान उधारकर्ता की भागीदारी

फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट अपने आप में पूरा नहीं करती है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश। उन दिशाओं में नहीं

एक से भागीदारी या निवेश के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान करें

फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उधारकर्ता, इस संभावना को जन्म देता है कि कुछ मामलों में, उधारकर्ता को फॉरेंसिक ऑडिट प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा जाता है।

सी. आर

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक और ऋणदाता बैंकों की ओर से, हमने श्री टा, भारत के सॉलिसिटर जनरल, श्री गोपाल जैन, वरिष्ठ वकील ईश बाबू एम आर और श्री जी एन रेड्डी, विद्वान वकील को सुना है। वकील प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर ऋण खाते के वर्गीकरण को चुनौती देते हैं।

निम्नलिखित कारणों से योग्यता:

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश आवश्यक थे

जमाकर्ताओं और बैंकों के हितों की रक्षा करना

बैंकों को कम किया जाता है। गुरु के खंड इसलिए धोखाधड़ी पर निर्देशों की व्याख्या उनके उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में की जानी चाहिए, यानी समय पर पता लगाना और सूचना का प्रसार करना और धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करना।

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के प्रावधानों का अर्थ निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए: (i) न्याय; (ii) पीड़ित पक्षों के प्रति निष्पक्षता; (iii) तर्कसंगतता; और (iv) शरारत के बीच आनुपातिकता।

और सुधारात्मक उपाय। यह देखते हुए कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश एक आर्थिक नीति का निर्णय है, इस न्यायालय को इसका अर्थ लगाते हुए अधिक अक्षांश का प्रयोग करना चाहिए

प्रावधान।

किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश मनमाना नहीं है। द.

वर्गीकरण केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मामले की सूचना देने के लिए किया जाता है। बैंक खातों में धोखाधड़ी की गतिविधियों की पहचान करने और उनकी जांच करने के लिए बैंकों के पास पहले से ही एक संरचित संगठनात्मक व्यवस्था है। बैंकों ने दर्ज कराई शिकायतें

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष, जो एक

जांच पड़ताल की। धोखाधड़ी पर अंतिम निर्णय इसके द्वारा दिया जाता है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अपराधिक कानून की प्रक्रिया को गति देने के चरण में लागू नहीं होते हैं। तब से ऋणदाता बैंक धोखाधड़ी वाले खातों के मामले में एक घायल पक्ष है, उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम को सुनवाई का अवसर दिए बिना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध की रिपोर्ट करने का अधिकार है।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

धोखाधड़ी करने वाला उधारकर्ता। धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं को कारण बताएँ नोटिस जारी करने से उन्हें पहले से चेतावनी दी जा सकती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच में बाधा आ सकती है।

धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं को बैंक वित्त का लाभ उठाने से रोकें

ई.

धोखाधड़ी पर दौत रहित कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी वाले उधारकर्ता को रोकने के लिए इस तरह का उपाय आवश्यक है। अन्य बैंकों में धोखाधड़ी करना।

आवन

यदि यह त्वरित कार्रवाई करने में बाधा डालता है। इसके अलावा, यह एक अलंघनीय नियम नहीं है कि व्यक्तिगत सुनवाई सभी में की जानी चाहिए। मामले।

एक ऋणकर्ता को विलफुल के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया

जी।

विलफुल डिफॉल्टर 1 13 पर मास्टर सर्कुलर के तहत चूककर्ता धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में खाने के वर्गीकरण की प्रक्रिया से काफी अलग है। इसलिए, जाह डेवलपर्स (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान अपील के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

D. विश्लेषण

डी. 1 विनियामक ढांचा

12. भारतीय रिज़र्व बैंक एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक की धारा 3 के तहत किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934। रिज़र्व बैंक का गठन केंद्र सरकार से मुद्रा के प्रबंधन को संभालने, बैंक नोट जारी करने को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भंडार रखने और मुद्रा के संचालन के उद्देश्य से किया गया है।

और भारत की ऋण प्रणाली। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों को प्रशासित करने का वैधानिक दायित्व सौंपा गया है। बी. आर. अधिनियम आर. बी. आई. को बैंकिंग के संबंध में विभिन्न शक्तियां देता है। कंपनियां जैसे लाइसेंस देना, निरीक्षण करना और निर्देश देना।

13. बी. आर. अधिनियम की धारा 35 ए आर. बी. आई. को बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। इस तरह के निर्देश वैधानिक प्रकृति के होते हैं। धारा 35 ए नीचे दी गई है:

13 विलफुल डिफॉल्टर्स पर मास्टर सर्कुलर, 2015 14 "बी. आर. एक्ट" [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 35 ए. निर्देश देने की रिजर्व बैंक की शक्ति (1)

जहाँ रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि

((क) लोक हित में; या

(एए)

बैंकिंग नीति के हित में; या

(ख)

किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को रोकने के लिए

जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से या जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित किया गया

बैंकिंग कंपनी, या

((ग)

किसी भी बैंकिंग कंपनी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

सामान्यतः,

आम तौर पर बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करना आवश्यक है।

या विशेष रूप से किसी बैंकिंग कंपनी को, वह समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो उसे उचित लगे, और बैंकिंग कंपनियों

या बैंकिंग कंपनी, जैसा भी मामला हो, बाध्य होगी

(2) रिजर्व बैंक, उसे किए गए अभ्यावेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, उप के तहत जारी किसी भी निर्देश को संशोधित या रद्द कर सकता है। धारा (1), और इस प्रकार किसी भी निर्देश को संशोधित या रद्द करने में -

ऐसी शर्तें लागू करें जो वह उचित समझे, जिसके अधीन

संशोधन या रद्द करने का प्रभाव पड़ेगा।

14. भारतीय रिजर्व बैंक 2016 से विभिन्न मुद्दों पर 'मुख्य निर्देश' जारी कर रहा है। इन निर्देशों में उस विशेष विषय पर निर्देश शामिल हैं। जब भी नीति में कोई बदलाव होता है तो मुख्य निर्देशों को अपडेट किया जाता है और इस तरह के बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दिखाई देते हैं। धारा 35 ए द्वारा

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी पर प्रमुख निर्देश 1 जुलाई 2016 को जारी किए ताकि पहले सात को समेकित और अद्यतन किया जा सके।

जून 2009 और जनवरी 2016 के बीच धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग और निगरानी के वर्गीकरण पर परिपत्र जारी किए गए। मास्टर डायरेक्शनसन धोखाधड़ी को 3 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया था। मुख्य निर्देशों का उद्देश्य नीचे दिया गया है:

" 1.3 उद्देश्य

ये निर्देश बैंकों को एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं ताकि वे धोखाधड़ी का जल्द पता लगा सकें और रिपोर्ट कर सकें और समय पर परिणामी कार्रवाई कर सकें जैसे कि जांच एजेंसियों को रिपोर्ट करना ताकि धोखाधड़ी करने वालों पर जल्दी मामला दर्ज किया जा सके, टीई बैंक ऑफ इंडिया और ओआरएस की जांच की जा सके।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

कर्मचारियों की जवाबदेही और प्रभावी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन। ये

निर्देशों का उद्देश्य सूचना के तेजी से प्रसार को सक्षम बनाना भी है

भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा विवरण पर बैंकों को

धोखाधड़ी, बेईमान उधारकर्ता और संबंधित पक्ष, के आधार पर

बैंकों की रिपोर्टिंग ताकि आवश्यक सुरक्षा उपाय/निवारक उचित प्रक्रियाओं और आंतरिक जाँच के माध्यम से उपाय

पेश किया जा सकता है और इस तरह से निपटने के दौरान सावधानी बरती जा सकती है

बैंकों द्वारा दल "।

15. उपरोक्त निर्देश विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जारी किए गए थे:

धोखाधड़ी का समय पर पता लगाना और रिपोर्ट करना; (ii) जांच एजेंसियों को धोखाधड़ी की जल्द और समय पर सूचना देना; (iii) धोखाधड़ी का तेजी से प्रसार करना।

धोखाधड़ी और धोखाधड़ी वाले उधारकर्ताओं के विवरण से संबंधित समझौता

और (iv) बैंकों द्वारा निवारक उपायों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना।

ई उद्देश्य खंड 2 में परिलक्षित होते हैं। 1 मास्टर दिशाओं का

ऑड्स:

" खंड 2। 1 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रमुख बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों (सी. एम. डी./सी. ई. ओ.) को ध्यान देना चाहिए।

"धोखाधड़ी रोकथाम और प्रबंधन कार्य" को सक्षम करने के लिए,

धोखाधड़ी के मामलों की प्रभावी जांच और

उचित समय पर शीघ्र और सटीक रिपोर्टिंग

विनियामक और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों सहित भारतीय रिजर्व बैंक। "

(जोर दिया गया)

16. खंड 2.2। 1 के प्रावधानों के आधार पर धोखाधड़ी को वर्गीकृत करता है

दण्ड संहिता, 1860:

" खंड 2.2। 1 रिपोर्टिंग में एकरूपता रखने के लिए, धोखाधड़ी होती है के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

मुख्य रूप से प्रावधानों

भारतीय दंड संहिता -

गबन और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन

ए।

जाली उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ी से नकदीकरण,

बी।

लेखा पुस्तकों में या काल्पनिक माध्यम से हेरफेर करना
लेखा और संपत्ति का रूपांतरण।

अनाधिकृत ऋण सुविधाओं को पुरस्कार के लिए या के लिए बढ़ाया गया

सी।

अवैध संतुष्टि

नकदी की कमी है।

डी।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखाधड़ी और जालसाजी

ई.

विदेशी मुद्रा से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन

एफ.

किसी भी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी जो विशिष्ट शीर्षों के अंतर्गत नहीं आती है

जी।

जैसा कि ऊपर बताया गया है।

17. खंड 3 बैंकों को केंद्रीय धोखाधड़ी का पूरा उपयोग करने की सलाह देता है।

धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों की समय पर पहचान, नियंत्रण, रिपोर्टिंग और शमन के लिए रजिस्ट्री 1.5 (धोखाधड़ी वाले खातों पर जानकारी साझा करने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया एक डेटाबेस)। उक्त निर्देशों का खंड 3.3 धोखाधड़ी के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने पर जोर देता है और समय सीमा का पालन न करने के लिए बैंकों को दंडित करता है:

" 3.3. 1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिपोर्टिंग प्रणाली उपयुक्त हो।

विलंबित और अपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्टों से बचा जाता है। बैंकों को करना होगा काम धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने में देरी के संबंध में कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें

आरबीआइ को।

3.3. 2 . धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी और इसके परिणामस्वरूप देरी कार्यप्रणाली के बारे में अन्य बैंकों को सचेत करना और

सावधानी सलाह/सी. एफ. आर. के माध्यम से जानकारी का प्रसार

बेईमान उधारकर्ताओं के खिलाफ समान परिणाम हो सकते हैं

धोखाधड़ी कहीं और की जा रही है। इसलिए बैंकों को चाहिए,

रिपोर्टिंग के लिए इस परिपत्र में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करें।

आर. बी. आई. को धोखाधड़ी के मामलों में ऐसा न करने पर वे दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

बैंकिंग विनियमन की धारा 47 (ए) के तहत निर्धारित कार्रवाई

अधिनियम, 1949 "।

(जोर दिया

गया)

18. धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश एक नियामक प्रदान करता है

चार प्रकार की धोखाधड़ी के लिए रूपरेखा: (i) चैप्टर IV धोखाधड़ी के प्रयास से संबंधित है; (ii) चैप्टर VII चेक से संबंधित धोखाधड़ी से संबंधित है; (iii) चैप्टर VIII ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है; और (iv) चैप्टर X चोरी, चोरी, डकैती और बैंक डकैती से संबंधित मामलों से संबंधित है। वर्तमान मामलों के समूह में विवाद ऋण धोखाधड़ी से निपटने वाले अध्याय VIII से संबंधित है।

19. अध्याय VI में कहा गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, धोखाधड़ी/धोखाधड़ी से जुड़े मामले

गबन हमेशा राज्य पुलिस या सी. बी. आई. को भेजा जाना चाहिए। अध्याय VIII अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि

15 " सी. एफ. आर. "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम. राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

बैंक एक सूचित राय बनाने के बाद जांच एजेंसियों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हैं। ऋण धोखाधड़ी से निपटने के लिए 7 मई 2015 के एक परिपत्र द्वारा रूपरेखा तैयार की गई थी। इस रूपरेखा का उद्देश्य खंड 8.2 में उल्लिखित किया गया है:

" 8.2 ढांचे का उद्देश्य

इस रूपरेखा का उद्देश्य रोकथाम, जल्दी पता लगाने, भारतीय रिजर्व बैंक को शीघ्र सूचना देने (प्रणाली स्तर के एकीकरण, निगरानी और विकास के लिए) से संबंधित पहलुओं पर बैंकों का ध्यान केंद्रित करना है।

प्रसार) और जांच एजेंसियां (स्थापना के लिए)

धोखाधड़ी वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही) और समय पर

कर्मचारी उत्तरदायित्व कार्यवाही की शुरुआत (निर्धारित करने के लिए) लापरवाही या मिलीभगत, यदि कोई हो) यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंकों के व्यवसाय के सामान्य संचालन और उनकी जोखिम लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कोई नई और भारी जिम्मेदारियां न हों।

किनारों पर रखा गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए,

फ्रेमवर्क ने कार्रवाई के साथ समय सीमा निर्धारित की है

एक बैंक। ऋण जीवन-चक्र में समय सीमा/चरणवार कार्यों से बैंक द्वारा पहचान करने के लिए लिए गए कुल समय को कम करने की उम्मीद है।

धोखाधड़ी और कानून प्रवर्तन द्वारा अधिक प्रभावी कार्रवाई में सहायता

एजेंसियां। धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना और आवश्यक

जिसे धोखाधड़ी के जारी रहने में शामिल किया जा सकता है।

20. खंड 8.3 प्रारंभिक चेतावनी संकेत 1 6 और लाल झंडे से संबंधित है।

खाते। 1 7 खंड 8.3 के अधीन। 1 , आर. एफ. ए. वह है जहाँ एक या अधिक ई. डब्ल्यू. एस. की उपस्थिति से धोखाधड़ी गतिविधि का संदेह पैदा होता है। ई. डब्ल्यू. एस. जिसे ऋण में गलत कार्यों के बारे में बैंक अधिकारियों को सचेत करना चाहिए

लेखा अनुलग्नक II में दिए गए हैं। इनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है:

ए। वैधानिक निकायों को निर्विवाद भुगतान में चूक

आई.

वार्षिक रिपोर्ट में घोषित;

बी। उच्च मूल्य के चेक का अनादर;

बकाया राशि के भुगतान में देरी;

ii.

परिसमापन के लिए अन्य बैंकों से आने वाली धनराशि

iii.

सामान्य पाठ्यक्रम को छोड़कर बकाया ऋण राशि;

16 " ईडब्ल्यूएस "

आर. एफ. ए. "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कई ऋणदाताओं से विशेष संपार्श्विक प्रभारित

iv.

मौजूदा शुल्क धारकों के एन. ओ. सी. के बिना;

संपार्श्विक प्रतिभूतियों के स्वामित्व पर विवाद; और

vi.

स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में महत्वपूर्ण मुद्दे।

vi.

21. ई. डब्ल्यू. एस. गलत काम के संकेत प्रदान करता है जो बाद में धोखाधड़ी साबित हो सकता है। ई. डब्ल्यू. एस. की उपस्थिति से एक बैंक को सतर्क कर दिया जाता है और संबंधित बैंक खाते की विस्तृत जांच शुरू करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। खंड 8.3 के अनुसार। 5 , खाते में संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी को बैंक द्वारा गठित धोखाधड़ी निगरानी समूह 1 8 18 को ई. डब्ल्यू. एस. के किसी भी प्रकटीकरण की तुरंत सूचना देनी चाहिए। यह खंड बैंकों को ईडब्ल्यूएस का संज्ञान लेने और आरएफए की विस्तृत जांच शुरू करने का निर्देश देता है।

22. खंड 8.8 उन स्थितियों से संबंधित है जहां एक बैंक एकमात्र ऋणदाता है। ऐसी स्थितियों में, एफ. एम. जी. को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है

पता करें कि क्या एक बैंक खाता जिसमें ई. डब्ल्यू. एस. देखा जाता है, उसे आर. एफ. ए. के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आर. एफ. ए. स्थिति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले बैंक को बाहरी लेखा परीक्षकों का उपयोग करने की अनुमति है। हालांकि, छह महीने के भीतर बैंक को या तो आर. एफ. ए. की स्थिति को हटाना होगा या जांच या फॉरेंसिक ऑडिट के अनुसार खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना होगा।

23. खंड 8.9 संघ या कई बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत ऋण देने से संबंधित है। खंड 8.9। 2 यह प्रदान करता है कि सभी बैंक जिनके पास

एम. बी. ए. के तहत वित्तपोषित एक उधारकर्ता को बाद की कानूनी कार्रवाइयों, अनुवर्ती कार्रवाई, विवरणों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक सुसंगत आधार पर सामान्य रूप से सहमत रणनीति के आधार पर समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। खंड 8.9। 4 और 8.9। 5 उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया प्रदान करें:

" 8.9. 4 किसी भी मानक खाते को वर्गीकृत करने का प्रारंभिक निर्णय या

आर. एफ. ए. या धोखाधड़ी के रूप में एन. पी. ए. खाता व्यक्तिगत स्तर पर होगा और इस बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वह सी. आर. आई. एल. सी. प्लेटफॉर्म पर खाते के आर. एफ. ए. या

धोखाधड़ी की स्थिति की रिपोर्ट करे ताकि अन्य बैंकों को सतर्क किया जा सके। यदि व्यक्तिगत बैंक स्तर पर इस स्तर पर ही खाते को सीधे धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है, तो बैंक पता चलने के 21 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को देगा और मामले की रिपोर्ट सीबीआई/पुलिस को भी देगा, जैसा कि कहा जा रहा है।

18 " एफएमजी "

19 " एम. बी. ए. "टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम। राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अब तक किया गया। इसके अलावा, आर. एफ. ए./धोखाधड़ी वर्गीकरण के 15 दिनों के भीतर, जिस बैंक ने खाते को लाल झंडी दिखाई है या धोखाधड़ी का पता लगाया है।

धोखाधड़ी संघ के नेता या एमबीए के तहत सबसे बड़े ऋणदाता को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जेएलएफ की एक बैठक बुलाने के लिए कहेगी। जे. एल. एफ. की इस प्रकार की बैठक बुलाई जानी चाहिए। इस तरह का अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर। यदि कोई व्यापक समझौता है, तो खाता होना चाहिए

धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत; अन्यथा कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बैंक के बीच समझौते के बहुमत नियम के आधार पर

कुल ऋण, खाते को सभी बैंकों द्वारा लाल झंडी दिखानी चाहिए और एम. बी. ए. के तहत संघ के नेता या सबसे बड़े ऋणदाता द्वारा शुरू या शुरू किए गए फॉरेंसिक ऑडिट के अधीन होना चाहिए। सभी बैंक, कई बैंकिंग व्यवस्था के संघ के हिस्से के रूप में, लागतों को साझा करेंगे और

इस तरह की जांच के लिए आवश्यक समर्थन।

8.9. 5 फॉरेंसिक ऑडिट को जेएलएफ की बैठक की तारीख से अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जो ऑडिट को अधिकृत करती है। फॉरेंसिक ऑडिट पूरा होने के 15 दिनों के भीतर, जेएलएफ फिर से बैठक करेगा और खाते की स्थिति पर निर्णय लेगा, या तो सर्वसम्मति से या बहुमत नियम के अनुसार जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। यदि निर्णय खाते को एक के रूप में वर्गीकृत करने का है धोखाधड़ी, आर. एफ. ए. की स्थिति को सभी बैंकों में धोखाधड़ी में बदल दिया जाएगा और उक्त निर्णय के एक सप्ताह के भीतर आर. बी. आई. और सी. आर. आई. एल. सी. मंच पर सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, आर. बी. आई. की रिपोर्टिंग के 30 दिनों के भीतर, बैंक को संघ/एम. बी. ए. में सभी बैंकों की ओर से सी. बी. आई. में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके लिए

उद्देश्य, यदि फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने वाला बैंक एक निजी है

सेक्टर बैंक, संघ/एम. बी. ए. में खाते में सबसे अधिक जोखिम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा सी. बी. आई. में शिकायत दर्ज की जाएगी। यदि संघ/एम. बी. ए. में कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है या यह किसी निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक द्वारा एकल बैंक ऋण है, तो निजी बैंक/विदेशी बैंक मौजूदा निर्देशों के अनुसार पुलिस को रिपोर्ट करेगा। यह यह पहले बैंक द्वारा पहले से दर्ज की गई शिकायत के अलावा होगा जिसने धोखाधड़ी का पता लगाया था और संघ/एमबीए को सूचित किया था।

(जोर दिया गया)

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. खंड 8.9। 4 यह निर्धारित करता है कि किसी खाते को आर. एफ. ए. या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रारंभिक निर्णय व्यक्तिगत बैंक के पास निहित है। एक बार जब बैंक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर देता है, तो यह उस बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह अन्य बैंकों को सतर्क करने के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट 20 प्लेटफॉर्म पर खाते में आर. एफ. ए. या धोखाधड़ी की स्थिति की रिपोर्ट करे। यदि व्यक्तिगत बैंक सीधे खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेता है, तो यह पता चलने के 21 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और मामले की रिपोर्ट सीबीआई/पुलिस को करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत बैंक संघ के नेता या सबसे बड़े ऋणदाता से पूछ सकता है।

एम. बी. ए. इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जे. एल. एफ. की एक बैठक बुलाएगा। जे. एल. एफ. की बैठक अनुरोध के 15 दिनों के भीतर बुलाई जानी है। प्राप्त हुआ। व्यापक सहमति होने पर जे. एल. एफ. किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। अन्यथा, खंड इंगित करता है कि कुल ऋण में कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले बैंकों के बीच एक समझौते के आधार पर, खाते को सभी बैंकों द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए और संघ के नेता या एमबीए के तहत सबसे बड़े ऋणदाता द्वारा शुरू या शुरू किए गए फॉरेंसिक ऑडिट के अधीन होना चाहिए।

25. खंड 8.9। 5 इसमें कहा गया है कि फॉरेंसिक ऑडिट को ऑडिट को अधिकृत करने वाली जेएलएफ की बैठक की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा करना होगा।

लेखापरीक्षा पूरा होने के 15 दिनों के भीतर, जे. एल. एफ. को खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने और आर. बी. आई. को इसकी रिपोर्ट करने का निर्णय लेना होता है। खंड में यह भी कहा गया है कि लेखा परीक्षा शुरू करने वाले बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने के 30 दिनों के भीतर संघ के सभी बैंकों की ओर से सी. बी. आई. में शिकायत दर्ज करानी होगी।

26. खंड 8.11 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शिकायत दर्ज कराने से संबंधित है। खंड 8.11। 1 धोखाधड़ी का पता लगाने पर बैंकों को तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता होती है। यह खंड बैंकों को शिकायत दर्ज करने में देरी से बचने का आदेश देता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दस्तावेजों का नुकसान, गवाहों की अनुपलब्धता, फरार उधारकर्ता, धन के लेन-देन का नुकसान और धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं द्वारा संपत्ति की चोरी हो सकती है।

27. धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपायों को खंड 8.12 में निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है:

8.12 धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपाय

8.12. 1 सामान्य तौर पर, जानबूझकर चूक करने वालों के लिए लागू दंडात्मक प्रावधान धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू होंगे, जिसमें प्रवर्तक निदेशक और कंपनी के अन्य पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं, जहां तक बैंकिंग से धन जुटाने का संबंध है।

20 " क्लिक "टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम. राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

वित्तीय संस्थान, सरकार के स्वामित्व वाली एन. बी. एफ. सी., निवेश संस्थान आदि, पांच साल की अवधि के लिए धोखाधड़ी की गई राशि के पूर्ण भुगतान की तारीख। इसके बाद

इस अवधि में, अलग-अलग संस्थानों को यह निर्णय लेना होता है कि ऐसे उधारकर्ता को ऋण दिया जाए या नहीं। दंडात्मक प्रावधान गैर-पूर्णकालिक निदेशकों (जैसे नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक) पर लागू होंगे। निदेशक) केवल दुर्लभतम मामलों में उनकी संलिप्तता के निर्णायक प्रमाण के आधार पर।

आर. एफ. ए. या धोखाधड़ी खातों के मामले में किया जाए। हालांकि, धोखाधड़ी/कदाचार के मामलों में जहां मौजूदा प्रवर्तक हैं नए प्रवर्तकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और उधारकर्ता कंपनी ऐसे पूर्व प्रवर्तकों/प्रबंधन, बैंकों से पूरी तरह से अलग हो जाती है और

जे. एल. एफ. पूर्व प्रवर्तकों/प्रबंधन के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई जारी रखने के पूर्वाग्रह के बिना, उनके व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्गठन पर विचार कर सकता है।

8.12. 4 उपरोक्त उधारकर्ता के अलावा-धोखेबाज, तीसरे पक्ष जैसे बिल्डर, गोदाम/कोल्ड स्टोरेज मालिक, मोटर वाहन/ट्रैक्टर डीलर, ट्रेवल एजेंट आदि और पेशेवर जैसे - वास्तुकार, मूल्यांकनकर्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि को भी जवाबदेह ठहराया जाता है यदि वे ऋण मंजूरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

धोखाधड़ी के अपराध का संवितरण या सुविधा प्रदान करना। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी में शामिल ऐसे पक्षों के विवरण की सूचना भारतीय बैंक संघ (आई. बी. ए.) को दें।

8.12. 5 आई. बी. ए. को रिपोर्ट करने से पहले, बैंकों को संबंधित तीसरे पक्ष की भागीदारी के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा और उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्रदान करना होगा। इस संबंध में बैंकों को सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी के आधार पर, आई. बी. ए., [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बदले में, प्रसार के लिए ऐसे तीसरे पक्ष की सावधानी सूची तैयार करें

बैंकों के बीच।

(जोर दिया

गया)

28. खंड 8.12। 1 यह प्रावधान करता है कि दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं

बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने के संबंध में धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं पर जानबूझकर चूक करने वालों पर लागू होगा। महत्वपूर्ण रूप से, इस खंड के तहत, धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं में ऋण लेने वाली कंपनी के प्रवर्तक, निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं। यह धोखाधड़ी वाले उधारकर्ताओं को बैंकिंग वित्त का लाभ उठाने से रोकता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विकास वित्तीय संस्थान, धोखाधड़ी की गई राशि के पूर्ण भुगतान की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए सरकारी स्वामित्व वाली एन. बी. एफ. सी., निवेश संस्थान आदि। पाँच साल की अवधि पूरी होने के बाद भी, यह व्यक्तिगत वित्तीय संस्थानों को तय करना है कि धोखाधड़ी वाले उधारकर्ताओं को ऋण देना है या नहीं, जिसमें शामिल हैं -

ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक और प्रवर्तक। इसके अतिरिक्त, खंड 8.12 के तहत। 2 , धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं को बैंकों और ऐसे अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पुनर्गठन या अतिरिक्त सुविधाओं के अनुदान से वंचित कर दिया जाता है।

डी. 2 ऑडी अल्टेरम पार्टम

29. हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

ये केवल कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं। वे महत्वपूर्ण दायित्वों का गठन करते हैं जिनका निर्णय लेने और निर्णय लेने वाले अधिकारियों द्वारा पालन करने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मनमानेपन के खिलाफ एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं।

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रक्रिया और सार दोनों के संदर्भ में कार्रवाई। प्राकृतिक विज्ञान के दो बुनियादी सिद्धांत

न्याय भारतीय न्यायशास्त्र में निहित है: (i) कार्यकारण में न्यायनिर्णायक पद, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए; और (ii) कार्यनिर्णायक पद, जिसका अर्थ है कि प्रशासनिक, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले सुना जाना चाहिए। अदालतें आम तौर पर एक वैधानिक की व्याख्या का समर्थन करती हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रावधान क्योंकि यह माना जाता है कि वैधानिक प्राधिकरणों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है। उक्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि

प्रकृति और उद्देश्य जिसके लिए शक्ति प्रदान की जाती है, और उस शक्ति के प्रयोग का अंतिम प्रभाव। 2 1
21 21 भारत संघ बनाम। कर्नल जे. एन. सिन्हा, (1970) 2 एस. सी. सी. 458 स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम।

30. जबकि उधारकर्ताओं का तर्क है कि बैंकों की कार्रवाई

धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उधारकर्ता खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, भारतीय रिजर्व बैंक और ऋणदाता बैंकों का तर्क है कि इन सिद्धांतों को आपराधिक अपराध की रिपोर्ट करने के चरण में लागू नहीं किया जा सकता है।

जाँच एजेंसियाँ। शुरुआत में, हम स्पष्ट करते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आपराधिक अपराध की रिपोर्ट करने के स्तर पर लागू नहीं होते हैं, जो इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई कानून की एक सुसंगत स्थिति है। भारत संघ में V. इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ डब्ल्यू. एन. चड्ढा ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रत्येक आपराधिक मामले में अभियुक्तों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने से "अदालत को निराशा होगी।

कार्यवाही, कानून की मांग के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने में बाधा डालना, न्याय के उद्देश्यों को विफल करना और संबंधित कानून के प्रावधान करना

जाँच निर्जीव, बेतुकी और आत्म-पराजय "। 22 पुनः, अंजू चौधरी बनाम मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। यूपी²³ राज्य ने दोहराया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सुनवाई के अधिकार का प्रावधान नहीं करती है।

31. धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों का अध्याय VIII प्रदान करता है

उधारकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए एक राय बनाने से पहले बैंकों द्वारा विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। उक्त अध्याय के तहत, ऋणदाता बैंकों को एक उधारकर्ता को रिपोर्ट करना होता है

उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के बाद सी. बी. आई. हालांकि, उधारकर्ता के खाते के वर्गीकरण से प्रवर्तन के साथ आपराधिक शिकायत की सूचना देना आसान नहीं होता है। प्राधिकरण; इसमें खंड 8.12 के तहत निर्धारित उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक परिणाम भी शामिल हैं।

32. मास्टर के तहत एक सूचित राय बनाने की प्रक्रिया

धोखाधड़ी पर निर्देश प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। आर. बी. आई. और ऋणदाता बैंकों ने भी अपनी लिखित दलीलों में इसे स्वीकार किया है। यह अब एक

कानून का स्थापित सिद्धांत कि ऑडी अल्टरम पार्टेम का नियम लागू होता है

न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के अलावा प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कानून में यह भी एक तय स्थिति है कि जब किसी प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या संस्था को नागरिक परिणाम मिलते हैं तो सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।

23 (2013) 6 एस. सी. सी. 384 24 ए. के. क्राईपाक बनाम। भारत संघ, (1969) 2 एस. सी. सी. 262; शासी निकाय, सेंट एंथोनी कॉलेज, शिलांग और अन्य बनाम। रेव. फा. शिलांग के पॉल पेद्रा, (1988) पूरक एस. सी. सी. 676; उमा नाथ पांडे और ओआरएस वी। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 40।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. उड़ीसा राज्य में v. डॉ. (मिस) बिनापानी देई 2 5, एक दो

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक प्राधिकारी जिसके पास दंडात्मक या हानिकारक कार्रवाई करने की शक्ति है, उसका कर्तव्य है कि वह सुनवाई का उचित अवसर दे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि एक प्रशासनिक

ऐसी कार्रवाई जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हों, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप की जानी चाहिए:

" 9. [.....] नियम कि एक पक्ष जिसका पूर्वाग्रह एक आदेश है पारित होने का इरादा सुनवाई का हकदार है जो न्यायिक न्यायाधिकरणों और निर्णय लेने के अधिकार के साथ निवेश किए गए व्यक्तियों के निकायों पर समान रूप से लागू होता है

नागरिक परिणामों से जुड़े मामलों पर। यह हमारे संवैधानिक ढांचे के मूलभूत नियमों में से एक है-कि प्रत्येक नागरिक

राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा मनमाने अधिकार के प्रयोग के खिलाफ संरक्षित। इसलिए न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य उस कार्य की प्रकृति से उत्पन्न होता है जिसे करने का इरादा है: इसे सुपर-एडेड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह को तय करने और निर्धारित करने की शक्ति है, तो न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य ऐसी शक्ति के प्रयोग में निहित है। यदि न्याय की अनिवार्यताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए आदेश दिया जाता है, तो आदेश अमान्य है। यह कानून के शासन की एक बुनियादी अवधारणा है और इसका महत्व किसी भी विशेष मामले में निर्णय के महत्व से परे है।

34. मेनका गांधी बनाम। भारत संघ की इस अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है -

नागरिक परिणाम देने वाले प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के कई फैसलों में इसे दोहराया गया है। कानून की स्थिर स्थिति को देखते हुए, अगला सवाल जो हमारे सामने उठता है, वह है 'नागरिक परिणाम' वाक्यांश का दायरा और परिभाषा।

25 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1269 26 (1978) 1 एस. सी. सी. 248 27
(1978) 1 एस. सी. सी. 405 28 (1993) 3 एस. सी. सी. 259 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ.
आर. एस. बनाम।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "हर वह चीज जो एक नागरिक के नागरिक जीवन को प्रभावित करती है, वह नागरिक परिणाम देती है।"

36. केनरा बैंक बनाम। वी. के. अवस्थी 2 9, दो-न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने नागरिक परिणामों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के इतिहास, दायरे और अनुप्रयोग को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया:

14. प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में बहुत बदलाव आया है

हमेशा किसी कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से। वे. निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निहित हो सकता है

और किसी दिए गए मामले में इसका संदर्भ क्या होना चाहिए, यह इस पर निर्भर करता है कि उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर काफी हद तक,

उस कानून की रूपरेखा जिसके तहत जांच की जाती है। पुराना।

न्यायिक अधिनियम और प्रशासनिक अधिनियम के बीच अंतर है

दूर चला गया। यहाँ तक कि एक प्रशासनिक आदेश जिसमें शामिल है

नागरिक परिणाम नियमों के अनुरूप होना चाहिए

प्राकृतिक न्याय। अभिव्यक्ति "नागरिक परिणाम"
इसमें न केवल संपत्ति या व्यक्तिगत का उल्लंघन शामिल है

अधिकार लेकिन नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक अभाव और गैर

आर्थिक क्षति। इसकी चौड़ी छतरी में सब कुछ आता है।

जो एक नागरिक के नागरिक जीवन को प्रभावित करता है।

(जोर दिया

गया)

न्यायिक विचार का एक सुसंगत स्वरूप है कि नागरिक

इसके परिणामस्वरूप न केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक अभाव और गैर-आर्थिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है।

नुकसान होता है। प्रत्येक आदेश या कार्यवाही जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं या नागरिक पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।

37. अगला सवाल जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ताओं को नागरिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

38. भारतीय रिज़र्व बैंक और ऋणदाता बैंकों ने तर्क दिया है कि नागरिक

खंड 8.12 में विचार किए गए परिणाम। 1 मास्टर दिशाओं का धोखाधड़ी उचित है। उक्त खंड के तहत, उधारकर्ता, सहित

29 (2005) 6 एस. सी. सी. 321 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी के प्रवर्तकों और निदेशकों को पांच साल की अवधि के लिए और संभवतः उससे आगे भी वित्तीय बाजारों और ऋण बाजारों से ऋण प्राप्त करने से रोक दिया गया है। रिजर्व बैंक और ऋणदाता बैंकों के अनुसार,

इस तरह के प्रतिबंध को जनहित के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया की कल्पना जनहित में की गई है, बैंकिंग प्रणाली की रक्षा के लिए, हम उधारकर्ताओं को होने वाले गंभीर नागरिक परिणामों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

39. धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों का खंड 8.12 उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपायों से संबंधित है। खंड 8.12। 1 प्रावधान करता है कि दंड

जानबूझकर चूक करने वालों पर लागू होने वाले प्रावधान धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू होंगे, जिनमें उधारकर्ता के प्रवर्तक और निदेशक भी शामिल हैं।

कंपनी। के तहत एक जानबूझकर चूक करने वाले पर लागू होने वाले परिणाम

जाह डेवलपर्स (ऊपर) में विलफुल डिफॉल्टरों पर मास्टर सर्कुलर निकाला गया है:

" 9. [.....] किसी व्यक्ति को जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद गंभीर परिणाम सामने आते हैं। ये परिणाम इस प्रकार हैं:

(क) किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी [पैरा 2.5 (क)]। (बी)

उद्यमियों/प्रवर्तकों को 5 साल की अवधि (पैरा 2.5 (ए)) के लिए संस्थागत वित्त से प्रतिबंधित किया जाएगा।

(ग) आपराधिक सहित कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

शिकायतें [पैरा 2.5 (बी)]।

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना।

विलफुल डिफॉल्टर के प्रबंधन को बदलना [पैरा 2.5 (सी)]।

(ड) विलफुल डिफॉल्टर के प्रवर्तक/निदेशक को इसके द्वारा शामिल नहीं किया जाएगा

एक अन्य उधार लेने वाली कंपनी [पैरा 2.5 (डी)]।

(च) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29-ए के अनुसार, एक विलफुल डिफॉल्टर समाधान आवेदक नहीं हो सकता है।

40. उपरोक्त परिणामों के अलावा, ऋणकर्ताओं को मुख्य निर्देशों के तहत निम्नलिखित परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धोखाधड़ी पर:

अ)

आर. एफ. ए. के मामले में कोई पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है या

धोखाधड़ी खाते (खंड 8.12.2)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

ख)

धोखाधड़ी से जुड़े समझौते पर कोई समझौता नहीं

उधारकर्ता को तब तक अनुमति दी जाती है जब तक कि शर्तें यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आपराधिक शिकायत जारी रखी जाएगी (खंड 8.12.3)

उपरोक्त परिणाम दर्शाते हैं कि एक का वर्गीकरण

विलफुल डिफॉल्टर्स पर मास्टर सर्कुलर के पैराग्राफ 3 में परिकल्पित इन-हाउस कार्यवाही के दौरान एक वकील द्वारा। विलफुल डिफॉल्टर्स पर मास्टर सर्कुलर के पैराग्राफ 3 में विलफुल डिफॉल्टर की पहचान के लिए दो-स्तरीय प्रक्रिया प्रदान की गई है। पहले चरण में, एक कार्यकारी निदेशक या समकक्ष की अध्यक्षता में एक पहली समिति और जिसमें दो अन्य वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं बैंक के अधिकारियों को, जानबूझकर चूक के साक्ष्य की जांच करने और यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि जानबूझकर चूक हुई है, संबंधित उधारकर्ताओं और प्रवर्तकों/पूर्णकालिक निदेशकों को उनके प्रस्तुतिकरण के लिए एक कारणदर्शक नोटिस जारी करना चाहिए। पहली समिति को विचार करना होगा

कारणों के साथ जानबूझकर चूक के तथ्य को दर्ज करने से पहले प्रस्तुतियाँ। यदि समिति इसे आवश्यक समझती है, तो वह व्यक्तिगत सुनवाई भी कर सकती है।

उधारकर्ता और उधार लेने वाली कंपनी के प्रवर्तक/पूर्णकालिक निदेशक को। दूसरा चरण यह है कि पहली समिति का आदेश है

समीक्षा समिति के रूप में जानी जाने वाली एक अन्य समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऋणकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया मास्टर [2023] 7 एस. सी. आर. के तहत परिकल्पित प्रक्रिया से अलग है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए धोखाधड़ी पर निर्देश। तथापि, खंड 8.12 के आधार पर। 1 धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के, जानबूझकर चूक करने वालों पर लागू दंडात्मक प्रावधान भी लागू होते हैं

धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ता। इस प्रकार, हालांकि एक विलफुल डिफॉल्टर की घोषणा के लिए अपनाई गई प्रक्रिया उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए परिकल्पित प्रक्रिया से अलग है, लेकिन उन्हें इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। परिणाम। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के खातों को कुछ अतिरिक्त परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो खंड 8.12 में निर्धारित किए गए हैं। 2 और 8.12। 3 . चूंकि दोनों परिपत्रों से निकलने वाले परिणाम समान हैं, जाह डेवलपर्स (ऊपर) में टिप्पणियाँ

किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का प्रभाव वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होगा। न्यायालय की टिप्पणियों को निकाला जाता है नीचे:

24. हालाँकि, हमारा विचार है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) है

वर्तमान मामले के तथ्यों में उस क्षण के रूप में आकर्षित किया गया

व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, इसका प्रभाव

व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष है और

तत्काल। यही कारण है कि कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं हैं।

किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अनुदान दिया जा सकता है, और उद्यमियों/प्रवर्तकों को संस्थागत रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।

पाँच साल के लिए वित्त। बैंक/वित्तीय संस्थान भी कर सकते हैं विलफुल डिफॉल्टर के प्रबंधन को बदलें, और

जानबूझकर चूक करने वाले का प्रवर्तक/निदेशक नहीं बनाया जा सकता है। किसी अन्य उधारकर्ता कंपनी के प्रवर्तक या निदेशक। समान रूप से,

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29-ए के तहत,

एक विलफुल डिफॉल्टर समाधान आवेदक होने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता है। इन कठोर परिणामों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि

संशोधित परिपत्र, जनहित में होने के कारण, होना चाहिए

उचित रूप से समझा गया।

(जोर दिया

गया)

जाह डेवलपर्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने मास्टर का अर्थ लगाया

विलफुल डिफाल्टर्स पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए परिपत्र। विशेष रूप से, यह निर्देश दिया गया था कि: (i) पहली समिति को जल्द से जल्द उधारकर्ता को अपना आदेश देना चाहिए; (ii) उधारकर्ता, उसके बाद, पहले के आदेश के खिलाफ एक लिखित अभ्यावेदन दायर कर सकता है।

समीक्षा समिति की समिति; और (iii) समीक्षा समिति को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए जो उधारकर्ता को प्रदान किया जाना चाहिए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

42. ऋणकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना

प्राथमिक बात यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई की मांग की जाती है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, प्रतिबंध समान है ऋण लेने वाले को ऋण लेने से रोकने के लिए काली सूची में डालना। ब्लैक लॉ डिक्शनरी 30 बताती है कि 'ब्लैकलिस्ट' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" विशेष परिहार, विरोध के लिए चिह्नित व्यक्तियों की एक सूची,

या सूची तैयार करने वालों की ओर से या उन लोगों की ओर से शत्रुता जो सूची तैयार करते हैं

जिसे प्रसारित करने का इरादा है; जहां एक व्यापार-संघ " ब्लैकलिस्ट किए गए कर्मचारी जो इसके नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं, या जहाँ

दिवालिया या अविश्वसनीय व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जाती है एक वाणिज्यिक एजेंसी या व्यापारिक संघ।

(जोर दिया गया)

इसी तरह, पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन 3 1 इस शब्द को परिभाषित करता है।

" काली सूची "इस प्रकार है:

जनता, या जनता के कुछ वर्ग को चेतावनी देंगे; ऐसे व्यक्ति जो श्रेय के योग्य नहीं हैं, या जिनके लिए यह उचित नहीं है

अनुबंध करने के लिए। इस प्रकार चूककर्ताओं की आधिकारिक सूची

स्टॉक एक्सचेंज एक काली सूची है। इस पर एक आदमी का नाम रखना

वैध कारण के बिना काली सूची कार्रवाई योग्य है; और आगे ऐसी सूची के प्रकाशन पर निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगाई जाएगी।

(जोर दिया गया)

43. एक काली सूची है: ((i) दिवालिया या अविश्वसनीय व्यक्तियों की सूची।

एक वाणिज्यिक एजेंसी या व्यापारिक संघ द्वारा प्रकाशित; और (ii) उन व्यक्तियों की सूची जो श्रेय के योग्य नहीं हैं, या जिनके साथ यह सलाह नहीं दी जाती है

अनुबंध करें। इस अदालत के समक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक और ऋणदाता बैंकों ने

30 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 5 थेडन (1979)
एनसाइक्लोपेडिक लॉ डिक्शनरी '(1997 संस्करण)

31 पी. रामनाथ अय्यर, 'द लॉ लेक्सिकॉन: द

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया कि उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त तक पहुँचने से रोकना

यह न केवल उन्हीं व्यक्तियों को अन्य बैंकों में धोखाधड़ी करने से रोकने के लिए आवश्यक है, बल्कि सार्वजनिक हित में बैंकों को बेईमान उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करने से रोकने के लिए भी आवश्यक है। खंड 8.12 के तहत किसी उधारकर्ता को छूट देना। 1 धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले को अविश्वसनीय और ऋण के लिए अयोग्य होने के कारण काली सूची में डालने के समान है। यह न्यायालय

लगातार यह माना गया है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

44. एसियन इन्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड v. पश्चिमी राज्य

बंगाल 3 2 32, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या कोई व्यक्ति सरकार द्वारा काली सूची में डालने से पहले सुनवाई के लिए नोटिस का हकदार है। यह अदालत ने कहा कि चूंकि काली सूची में डालने से काली सूची में डाले गए व्यक्ति के विशेषाधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए निष्पक्ष खेल के मूल सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए:

" 20. ब्लैकलिस्टिंग में किसी व्यक्ति को रोकने का प्रभाव पड़ता है

कानूनी संबंध में प्रवेश करने का विशेषाधिकार और लाभ सरकार लाभ के उद्देश्यों के लिए। तथ्य यह है कि एक विकलांगता है

ब्लैकलिस्टिंग के क्रम द्वारा बनाया गया संकेत देता है कि प्रासंगिक

प्राधिकार एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि है। की मूल बातें निष्पक्ष खेल के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को एक

उसे काली सूची में डालने से पहले अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर।

45. जोसेफ विलांगंदन बनाम। कार्यकारी अभियंता 3 3, मुद्दा

दोनों न्यायाधीशों के समक्ष एक सरकारी ठेकेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना सरकार के साथ कोई और अनुबंध करने से रोकने से संबंधित था। वहाँ नोटिस का सामग्री वाक्य इस प्रकार पढ़िए:

हो सकता है कि आपके जोखिम और नुकसान पर अन्य तरीकों से व्यवस्था न की जाए आपको चूककर्ता के रूप में प्रतिबंधित करने के बाद एजेंसियां। '

(मूल पर

जोर दें)

इस न्यायालय ने एसियन उपकरण में कानून की स्थिति को लागू किया और

केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर) ने यह अभिनिर्धारित किया कि कार्यकारी अभियंता को संविदाकार को प्रतिबंध की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

32 (1975) 1 एस. सी. सी. 70 33 (1978) 3 एस. सी. सी. 36 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

46. रघुनाथ ठाकुर बनाम। बिहार राज्य 3 4 34, दो-न्यायाधीशों की पीठ

सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही काली सूची का आदेश जारी किया जाना चाहिए प्राकृतिक न्याय:

" 4. [.....] जहाँ तक यह तर्क है कि कोई आवश्यकता नहीं है

विशेष रूप से किसी भी सूचना देने से संबंधित है, प्रतिवादी है

सही है। लेकिन यह कानून के शासन का एक निहित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश सिविल परिणाम निम्नलिखित के बाद ही पारित किया जाना चाहिए:

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। यह महसूस करना होगा कि काली सूची में डाल दिया गया है

व्यावसायिक उद्यमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति का नागरिक परिणाम होता है।

किसी भी घटना में संबंधित व्यक्ति के भविष्य के व्यवसाय के लिए।

भले ही नियम ऐसा व्यक्त नहीं करते हैं, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है

प्राकृतिक न्याय कि किसी भी आदेश से प्रभावित पक्षों को अधिकार होना चाहिए

सुनाया जाना और आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करना। [...] "

47. गोरखा सुरक्षा सेवा बनाम। सरकार (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 3 5,

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा कारण दर्शाओ नोटिस के प्रपत्र और सामग्री से संबंधित है जिसे नोटिसकर्ता को काली सूची में डालने से पहले दिया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने का आदेश कलंकित करने वाला है। प्रासंगिक अवलोकन नीचे निकाला गया है:

16. यह पक्षों का एक सामान्य मामला है कि काली सूची में डालने वाले को

काली सूची में डालने की मांग का एक वैध और ठोस तर्क है इसके पीछे। काली सूची में डालने के साथ, कई नागरिक और/या बुराई

परिणाम सामने आते हैं। इसे "नागरिक मृत्यु" के रूप में वर्णित किया गया है

वह व्यक्ति जिसे काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है। इस तरह

एक आदेश प्रकृति में कलंकित है और ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है

सरकारी निविदाओं में भाग लेने से जिसका अर्थ है

उसे सरकारी अनुबंधों के पुरस्कार से वंचित करना।

(जोर दिया

गया)

48. उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रभाव पड़ता है

उधारकर्ता को संस्थागत वित्त तक पहुँचने से रोकने के लिए 34 (1989) 1 एससीसी 229 35
(2014) 9 एससीसी 105 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यवसाय का उद्देश्य। इसके महत्वपूर्ण नागरिक परिणाम भी होते हैं क्योंकि यह उधारकर्ता के व्यवसाय के भविष्य को खतरे में डालता है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत खंड 8.12 के तहत उधारकर्ता को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने से पहले सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। 1 धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश। किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई न केवल उधारकर्ता के व्यवसाय और सद्भावना को प्रभावित करती है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करती है।

49. महाराष्ट्र राज्य में V. शासन के लिए जनता की चिंता

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार को प्रभावित करने वाले किसी भी प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के नागरिक परिणाम होते हैं। इसलिए, ऐसी स्थितियों में प्राकृतिक के सिद्धांत

न्याय खेल में आएगा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्राधिकरण का कोई भी आदेश या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद लिया जाना चाहिए:

" 41. इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कोई भी होने का हकदार है और

संभाल कर रखें।

अपनी प्रतिष्ठा और उसकी रक्षा करने का भी अधिकार है। किसी भी मामले में

व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के क्षेत्र में यात्रा करना प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है उसे इस मामले में अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति का सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार

प्रतिकूल होने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का

टिप्पणी को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है और उसी का उल्लंघन है न्यायिक समीक्षा की जांच का सामना करना पड़ेगा।

50. रिजर्व बैंक और ऋणदाता बैंकों ने पीयरलेस जनरल पर भरोसा किया है।

वित्त और निवेश कंपनी लिमिटेड V. भारतीय रिजर्व बैंक 3 7, जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक 3 8 38, और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक 3 9 39 यह प्रस्तुत करने के लिए कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश एक वैधानिक विनियमन और आर्थिक नीति पर निर्णय के समान हैं, जो होना चाहिए

सम्मान का एक स्तर दिया गया।

51. आर. बी. आई. की मास्टर निर्देश जारी करने की क्षमता

इन अपीलों में धोखाधड़ी विवाद का विषय नहीं है। आर. बी. आई. के पास अपने अनुमान में आर्थिक उपायों को निर्धारित करने और उन्हें तैयार करने की शक्ति है।

36 (2007) 3 एस. सी. सी. 587 37 (1992) 2 एस. सी. सी. 343 38 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1371 39 (2020) 10 एस. सी. सी. 274 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

बैंकिंग का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जनहित में

कंपनियाँ। हालांकि मुद्दा यह है कि बैंकिंग कंपनियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के निर्णय का कार्यान्वयन कानून की उचित प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के बाद होने वाले नागरिक परिणाम उधारकर्ता के हितों के लिए गंभीर और प्रतिकूल हैं। निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

डी. 3 ऑडी अल्टरम पार्टम का कोई निहित बहिष्करण नहीं

52. आर. बी. आई. और ऋणदाता बैंकों ने तर्क दिया है कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश निहित रूप से सुनवाई के अधिकार को बाहर करते हैं। धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों का उद्देश्य समय पर पता लगाना और

अन्य बैंकों को सतर्क करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देना। निर्देश किसी ऐसे तीसरे पक्ष को सुनने के अवसर पर विचार करते हैं जो धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी उधारकर्ता को सुनवाई के लिए प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, यह अग्रह किया जाता है कि उधारकर्ताओं की सुनवाई को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा जाए।

53. धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट रूप से उधारकर्ताओं को उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई के अधिकार को बाहर नहीं करते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक कानून या एक अधिसूचना में पड़ा जा सकता है जहां यह एक पक्ष को सुनवाई का अवसर देने पर चुप है जिसके अधिकार और हित पारित किए जाने वाले आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है।

54. स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में। भारत संघ, मुद्दा यह था कि क्या केंद्रीय

सरकार को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-ए (1) (ए) के तहत एक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संभालने से पहले ऑडी अल्टरम पार्टम की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक था। आर. एस. सरकारिया, जे. ने अपने और डी. ए. देसाई, जे. के बहुमत के लिए बोलते हुए कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:

44. संक्षेप में, सामान्य सिद्धांत-जैसा कि एक समान अनुप्रयोग के एक पूर्ण नियम से अलग है, ऐसा लगता है कि जहां एक

कानून, शब्दों में, पूर्व सुनवाई के इस नियम को बाहर नहीं करता है लेकिन

40 (1981) 1 एस. सी. सी. 664

41 " आईडीआर अधिनियम, 1951 "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पूर्ण समीक्षा के बराबर निर्णय के बाद की सुनवाई पर विचार करता है गुण-दोष पर मूल
आदेश का, तब ऐसा कानून होगा -

पूर्व में ऑडी अल्टरम पार्टिम नियम को बाहर करने के रूप में समझा गया निर्णयात्मक चरण।
इसके विपरीत, यदि कानून प्रदान करता है

एक पूर्व-निर्णय देने के संबंध में शक्ति चुप है

प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय में नागरिक परिणाम शामिल हैं गंभीर प्रकृति का, और योग्यता
पर कोई पूर्ण समीक्षा या अपील नहीं

उस निर्णय के खिलाफ प्रदान किया जाता है, अदालतें अत्यधिक होंगी इस तरह के कानून को
कर्तव्य को छोड़कर समझने के लिए अनिच्छुक

यहाँ तक कि सभी औपचारिक श्रव्यता को कम से कम सुनाने का

निर्णय लेने से पहले के चरण में ट्रेपिंग और डिलेटरी विशेषताएँ,

जब तक, व्यावहारिक रूप से नहीं देखा जाता है, यह लकवाग्रस्त कर देगा प्रशासनिक प्रगति या
अत्यधिक आवश्यकता को विफल करना

शीघ्रता। संक्षेप में, निष्पक्ष खेल का यह नियम नहीं होना चाहिए बहुत ही असाधारण परिस्थितियों
में छोड़ दिया जाता है जहाँ

इस मूल नियम को अधिकतम करने के लिए हर संभव प्रयास जहाँ तक संभव हो, स्थितिजन्य
संशोधनों के साथ। लेकिन, याद करने के लिए

तथापि, भगवती जे. के शब्द, जो इसके मूल में हैं, बने रहने चाहिए:

सुना जा रहा है और सुनवाई एक वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए और नहीं एक खाली जनसंपर्क
अभ्यास।

(जोर दिया गया)

55. स्वदेशी में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुख्य बिंदु

ऑन मिल्स (सुप्रा) यह था कि क्या वाक्यांश का उपयोग "तत्काल" है।

आई. डी. आर. अधिनियम की धारा 18-ए. ए. (1) (ए) के तहत अनिवार्य है।

ऑडी अल्टरम पार्टिम नियम का अनुप्रयोग करें। सरकारिया, जे आयोजित

वह अभिव्यक्ति "तत्काल कार्रवाई", जिसका अर्थ कानून के समग्र उद्देश्य और कारणों के आलोक में किया गया
है, आवश्यक रूप से इंगित नहीं करता है

पूर्व सुनवाई की आवश्यकता को बाहर करने का आग्रह। अदालत ने कहा कि वह वाक्यांश का उपयोग पालन करने के कर्तव्य को बाहर नहीं करता है अल्टरम पार्टिम नियम:

" 77. दूसरा कारण जो कमोबेश एक पहलू है

सबसे पहले

यह मानने के लिए कि केवल शब्द का उपयोग

आवश्यक रूप से और पूरी तरह से पूर्व को बाहर नहीं करता है अनुप्रयोग, यह है कि तत्काल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम।

ऑडी अल्टरम पार्टिम नियम का

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

या त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता एक स्थितिजन्य तथ्य है

गिरावट पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना के साथ एक सीधा संबंध

उत्पादन में। और, ऐसी संभावना और कार्रवाई की तात्कालिकता

प्रभावित करना। . . धारा 18-ए. ए. (1) (ए) में प्रयुक्त उत्पादन हैं -
स्थितियों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को समझने के लिए पर्याप्त लचीला

एक से लेकर जहाँ होने की संभावना है

पकड़ी गई घटना की निकटता उस स्थान तक है जहाँ यह हो सकता है

निकट भविष्य में किसी समय होने का उचित अनुमान लगाया जा सकता है

भविष्य। अत्यधिक तात्कालिकता के मामले जहाँ धारा के तहत कार्रवाई की जाती है

18 - ए (1) (ए) उत्पादन में गिरावट और परिणामी क्षति को रोकने के लिए

जनहित के लिए, इसमें कोई देरी नहीं होगी, यह दुर्लभ होगा। में।

अधिकांश मामलों में, जहाँ तात्कालिकता इतनी चरम नहीं है, यह व्यावहारिक है
के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच समायोजन और संतुलन बनाने के लिए

जल्दी करो और सुनो। "

(जोर दिया

गया)

सरकारिया, जे ने कहा कि एक उपक्रम का मालिक हकदार है

निर्णय पूर्व स्तर पर निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्योंकि धारा 18ए-ए(1) (ए) के तहत केंद्र सरकार की
अधिकार लेने की शक्ति दूरगामी है और मालिकों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

56. मंगीलाल वी. मध्य प्रदेश राज्य 1 2, एक दो-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, भले ही
क्रानून इस संबंध में चुप हो। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को
इंगित करने के लिए एक वैधानिक मौन लिया जाना चाहिए जहाँ पक्षों के पर्याप्त अधिकार प्रभावित होते हैं:

10. भले ही कोई क्रानून शांत हो और कोई सकारात्मक शब्द न हो

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में, हो सकता है

पक्षों को सुनने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में कुछ भी गलत नहीं है

जिनके अधिकार और हित प्रभावित होने की संभावना है

आदेश जो पारित किए जा सकते हैं, और इसे एक आवश्यकता बनाते हुए

निर्णय लेने से पहले एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करें, जब तक कि

कानून अन्यथा प्रदान करता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

कानून के खाली अंतराल में पढ़ा जाना चाहिए,

जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट जनादेश न हो। कोई फॉर्म या प्रक्रिया को कभी भी बाहर करने की अनुमति दी जानी चाहिए

वादी के बचाव या पक्ष की प्रस्तुति। यहां तक कि

42 (2004) 2 एस. सी. सी. 447 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रियात्मक कानूनों में प्रावधान का अभाव, प्रत्येक में शक्ति निहित है
न्यायिक या अर्ध-न्यायिक चरित्र का न्यायाधिकरण/न्यायालय, जिसे अपनाना है
प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तौर-तरीके
और अपने कर्तव्यों का बेहतर और उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष खेल।
प्रक्रिया मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

व्यक्त प्रावधान द्वारा इसके आवेदन की सीमा के बावजूद
एक दी गई स्थिति में उस संबंध में। यह हमेशा एक पोषित रहा है

सिद्धांत। जहाँ कानून पालन के बारे में चुप है
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से, इस तरह की वैधानिक खामोशी है

प्राकृतिक के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए लिया गया
न्याय जहाँ पक्षों के पर्याप्त अधिकार हैं
प्रभावित हुए। प्राकृतिक न्याय का अनुप्रयोग बन जाता है
अनुमानित, जब तक कि व्यक्त शब्दों द्वारा बहिष्कृत नहीं पाया जाता है
कानून या आवश्यक इरादा। इसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है।
या न्याय की विफलता को रोकने के लिए। प्राकृतिक सिद्धांत
न्याय कानून का स्थान नहीं लेता है, बल्कि इसका पूरक है। ये

नियम केवल उन क्षेत्रों में काम करते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून के दायरे में
नहीं आते हैं।

वे अंत का एक साधन हैं और अपने आप में अंत नहीं हैं। [.....]

(जोर दिया

गया)

57. उपरोक्त कानूनी स्थिति के विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक और ऋणदाता

बैंकों ने तर्क दिया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उन मामलों में बाहर रखा जा सकता है जहां शीघ्रता
या अनिवार्यता की आवश्यकता होती है कार्रवाई। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, भारतीय रिजर्व बैंक
और बैंकों ने अजीत कुमार नाग बनाम पर भरोसा किया है। महाप्रबंधक (पी. जे.), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।
लिमिटेड 1 3 43, जो बदले में भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर निर्भर था।
तुलसीराम पटेल। 4 तुलसीराम पटेल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि पूर्व सूचना के अधिकार और

सुनवाई के अवसर को बाहर रखा जा सकता है यदि इस तरह के अधिकार की अनुमति देने से त्वरित कार्रवाई करने में बाधा आएगी:

101. [.....] जहाँ तक ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम का संबंध है,

इंग्लैंड और भारत दोनों में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ एक

पूर्व सूचना का अधिकार और सुनवाई का अवसर

आदेश पारित होने से त्वरित कार्रवाई करने में बाधा आएगी, जैसे कि

अधिकार को बहिष्कृत किया जा सकता है। इस अधिकार को भी बाहर किया जा सकता है जहाँ की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति, उसका उद्देश्य और उद्देश्य

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की योजना इसके बहिष्करण की गारंटी देती है;

43 (2005) 7 एस. सी. सी. 764

44 (1985) 3 एससीसी 398 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

न ही ऑडी अल्टरम पार्टम नियम को लागू किया जा सकता है यदि इसे आयात करने से प्रशासनिक प्रक्रिया को पंगु बनाने का प्रभाव पड़ेगा या जहां शीघ्रता या कार्रवाई करने की तात्कालिकता की आवश्यकता होगी।

माँगे, [.]

58. ऋणकर्ताओं ने खंड 8.9 पर ध्यान दिया है। 6 धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश जिसके अनुसार एक व्यक्तिगत बैंक द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने से लेकर जे. एल. एफ. द्वारा धोखाधड़ी की घोषणा तक की पूरी कवायद छह महीने के भीतर पूरी की जानी है। खंड 8.9। 6 इस प्रकार प्रदान करता है:

" 8.9. 6 यह ध्यान दिया जा सकता है कि पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत कुल समय उस तारीख से छह महीने है जब पहले सदस्य बैंक ने खाते को आर. एफ. ए. या धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया था।

क्लिक प्लेटफॉर्म "।

59. के आई शेफर्ड बनाम। भारत संघ, इस न्यायालय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई समामेलन योजनाओं की वैधता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जिसके तहत तीन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय किया गया था। विलय के समय, निजी बैंकों के कुछ कर्मचारियों को नौकरी से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके खिलाफ कदाचार के आरोपों के कारण हस्तांतरणकर्ता बैंकों द्वारा उनकी सेवाओं को नहीं लिया गया था। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि समामेलन की पूरी प्रक्रिया को सांविधिक रूप से 6 महीने के भीतर पूरा करना आवश्यक था, इस न्यायालय ने कहा कि उक्त समय सीमा प्रभावित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर देने की गुंजाइश प्रदान करती है:

15. [...] हम नहीं सोचते कि मामले के तथ्यों में यह मानने का कोई औचित्य है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों को समय सीमा के कारण आवश्यक निहितार्थ से हटा दिया गया है। जिस पर

दूसरी ओर हमारा विचार है कि कानून द्वारा सीमित समय योजना को अंतिम रूप देने से पहले इच्छित बहिष्कृत कर्मचारियों को विस्तारित करने का अवसर प्रदान करता है ताकि स्थिति के अनुरूप सुनवाई की व्यवस्था के एक खंड के समक्ष की जा सके।

कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है।

60. स्वदेशी कॉटन मिल्स (ऊपर) और के. आई. शेफर्ड (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय दर्शाता है कि किसी स्थिति की आवश्यकता प्रासंगिक है। न्यायालय को सिद्धांतों को पढ़ने के पक्ष में झुकना चाहिए

प्राकृतिक न्याय जब एक नियामक मौन का सामना करना पड़ता है। किसी भी बहिष्करण को सबसे संकीर्ण संभव सीमाओं तक सीमित किया जाना चाहिए। का आवेदन

45 (1987) 4 एससीसी 431 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के दौरान उधारकर्ताओं की भागीदारी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केवल उधारकर्ताओं से जानकारी लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है क्योंकि उधारकर्ताओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए।

62. केशव मिल्ल्स कं. लिमिटेड बनाम। भारत संघ, यह न्यायालय कंपनी के मामलों की पूरी जांच पूरी होने के बाद आई. डी. आर. अधिनियम, 1951 के तहत सरकार द्वारा एक कंपनी के अधिग्रहण के मुद्दे पर विचार कर रहा था। मुद्दा यह था कि क्या एक की रिपोर्ट

प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जाँच निकाय होना चाहिए
संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया

प्राधिकारी द्वारा लेने से पहले

उस रिपोर्ट पर निर्णय। एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने का निर्णय लेते समय, इस न्यायालय ने कहा कि कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ

प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए संबंधित पक्ष को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

46 (1973) 1 एससीसी 380 टीई बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

21. हमारी राय में कोई सामान्य सिद्धांत निर्धारित करना संभव नहीं है।

इस सवाल पर कि क्या किसी जांच निकाय की रिपोर्ट

इससे पहले कि प्राधिकरण उस रिपोर्ट पर निर्णय ले। इसका जवाब तथ्यों पर निर्भर रहना चाहिए और

इस प्रश्न के लिए भी हमेशा

मामले की परिस्थितियाँ। इसकी कोई संभावना नहीं है कि कि रिपोर्ट नहीं दी जाती

कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जब तक

संबंधित पक्ष कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

उस कार्रवाई के बारे में जो सरकार करती है या करने का प्रस्ताव करती है पर। क्या रिपोर्ट होनी चाहिए

उस रिपोर्ट के आधार

सुसज्जित या नहीं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए।

उस मामले के गुण-दोष पर मामला। हमें कोई संदेह नहीं है कि

तत्काल मामले में जाँचकर्ता की रिपोर्ट का खुलासा न करना

समिति ने किसी भी तरह का पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया है

याचिकाकर्ता।

(जोर दिया गया)

63. स्वदेशी कॉटन मिल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि

कोई भी एकत्र किए गए साक्ष्य की व्याख्या करने के अवसर का हकदार है।

प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए:

85. यह विवाद ठीक से स्थापित प्रतीत नहीं होता है। सबसे पहले,

यह दस्तावेजी साक्ष्य, सबसे अच्छा, दिखाता है कि कंपनी थी

ऋण में और इसकी कुछ "इकाइयों" की परिसंपत्तियों का अनुमान लगाया गया था।

या उन ऋणों की प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया। मौका दिया गया।

कंपनी ने समझाया होगा कि इसके परिणामस्वरूप

यह उन आवश्यक शर्तों में से एक है जिनके संबंध में सरकार कार्रवाई करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए।

धारा 18 ए-ए (1) (ए) के तहत

दूसरा, प्राकृतिक न्याय के नियम में क्या आवश्यक है
थी कि कंपनी

इस मामले की परिस्थितियाँ केवल यह नहीं

समझाने का मौका दिया जाना चाहिए था

इसके खिलाफ सबूत, लेकिन सूचित होने का अवसर भी

अधिग्रहण की प्रस्तावित कार्रवाई और यह दर्शाने के लिए कि यह क्यों
न लें।

(जोर दिया गया)

64. ऑडी अल्टरम पार्टमें में सेवा सहित कई पहलू हैं।

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रही आदेश पारित किया जा सकता है [2023] 7 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और एकत्र किए गए साक्ष्य की व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना। तुलसीराम में पटेल (ऊपर), इस न्यायालय ने ऑडी अल्टरम के व्यापक आयाम की व्याख्या की

हिस्सा:

इन अपीलों और रिट याचिकाओं में, अर्थात्, ऑडी अल्टरम पारटेम नियम, अपने पूर्ण आयाम में इसका मतलब है कि एक व्यक्ति

जिनके खिलाफ उसके पूर्वाग्रह का आदेश पारित किया जा सकता है

उनके खिलाफ आरोपों और आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए

उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

अतः, मौखिक या दोनों तरह से साक्ष्य जानने का अधिकार है। वृत्तचित्र, जिसके द्वारा मामले को तय करने का प्रस्ताव है

उसके खिलाफ, और उन दस्तावेजों का निरीक्षण करना जिन पर भरोसा किया जाता है

उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य से,

गवाह जो उसके खिलाफ सबूत देने वाले हैं

उनकी जाँच करें, और अपने स्वयं के साक्ष्य का नेतृत्व करें, दोनों मौखिक और वृत्तचित्र, उनके बचाव में। निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया

तथापि, न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है। कानून, क्योंकि कारणों के न्यायिक निर्णय में कई शामिल हैं

प्रक्रिया और साक्ष्य के तकनीकी नियम जो अनावश्यक हैं

अर्ध-न्यायिक या न्यायिक में ऑडी अल्टरम पारटेम नियम का अर्थ प्रशासनिक जाँच। [.....]

(जोर दिया गया)

65. ऑडी अल्टरम पारटेम, इसलिए, निहित है कि एक इकाई के खिलाफ

जिनका सबूत एकत्र किया जाता है उन्हें: ((i) उसके विरुद्ध साक्ष्य की व्याख्या करने का अवसर प्रदान किया जाए; (ii) प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए, और (iii) यह प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए कि प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इसलिए, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केवल उधारकर्ता की भागीदारी प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय में ऋणदाता बैंकों द्वारा तथ्यों और कानून के प्रति विवेक का उचित अनुप्रयोग शामिल है। ऋणदाता बैंकों को, या तो व्यक्तिगत रूप से या जेएलएफ के माध्यम से, यह तय करना होता है कि क्या किसी उधारकर्ता ने ऋण समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है।

और इस तरह के निर्धारण के आधार पर ऋणदाता बैंक उचित उपचार की तलाश कर सकते हैं। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मांग करते हैं कि

उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, और धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

D. 4 संवैधानिक वैधता के लिए चुनौती

66. उधारकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मास्टर निर्देश

बैंकों को दिशाहीन और बेलगाम शक्तियां प्रदान करने के लिए धोखाधड़ी को मनमाना और असंवैधानिक के रूप में समाप्त करना होगा। प्रस्तुतिकरण का प्रतिकार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और ऋणदाता बैंकों ने दिल्ली क्लॉथ मिल्स एंड जनरल मिल्स बनाम में निर्णय पर भरोसा किया है। भारत संघ 47 प्रस्तुत करेगा

कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के प्रावधान मनमाने नहीं हैं क्योंकि उनका उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। यह आगे तर्क दिया गया कि अदालतों को आर्थिक नीति निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनके विवेक को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से विकृति, मनमानेपन या दुर्भावना न हो।

67. आर. बी. आई. को ऐसे सभी उपाय करने का अधिकार है जो इस प्रकार हैं -

बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक। इसलिए, धोखाधड़ी पर प्रमुख निर्देश बैंकों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, जो उधारकर्ताओं द्वारा ऋण समझौतों के उल्लंघन के मामले में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करके और उधारकर्ताओं को आगे संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोककर उचित उपाय कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी नीतिगत निर्णय जो किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर नागरिक परिणामों पर विचार करता है, अगर प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो मनमाने होने के लिए चुनौती दी जा सकती है।

68. ई पी रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य 48, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि एक मनमानी राज्य कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। पुनः, मेनका गाँधी (ऊपर) में इस न्यायालय ने दोहराया कि गैर-मनमानेपन का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में व्याप्त है। चार आधारों पर अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक दुर्बलताओं के लिए एक प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण किया जा सकता है: (i) अनुचितता या तर्कहीनता; (ii) अवैधता; (iii) प्रक्रियात्मक

अनुचितता; 4 9 और (iv) आनुपातिकता। हालाँकि, इस तरह की न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने में कमी का पता लगाने तक सीमित है। प्रक्रिया, और प्रशासक द्वारा की गई पसंद की शुद्धता नहीं।

50

69. कार्रवाई में निष्पक्षता के लिए ऐसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जो अनुमति देती हैं

मौलिक अधिकार की हानि न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग है और इसका गठन करता है

47 (1983) 4 एससीसी 166

48 (1974) 4 एस. सी. सी. 3 49 एपी राज्य बनाम। मैकडोवेल, (1996) 3 एस. सी. सी. 709; ओम कुमार बनाम। भारत संघ (2001) 2 एस. सी. सी. 386 50 अध्यक्ष और प्रबंध

निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम। पी. सी. कक्कड़ (2003) 4 एस. सी. सी. 364 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 14 के तहत परिकल्पित प्रक्रियात्मक औचित्य का एक महत्वपूर्ण पहलू। ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम को अनुच्छेद 14 में निहित गारंटी के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। तुलसीराम पटेल (ऊपर) मामले में इस अदालत की एक संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अदालत ने माना कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में किसी भी राज्य की कार्रवाई से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है:

" 95. इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सामने आए हैं।

अनुच्छेद में निहित गारंटी के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त

14 इसके द्वारा दी गई नई और गतिशील व्याख्या के कारण

समानता की अवधारणा के लिए न्यायालय जो विषय है -

उस लेख को। संक्षेप में, शब्दांश इस प्रकार चलता है: एक नियम का उल्लंघन

प्राकृतिक न्याय का परिणाम मनमानेपन में होता है जो समान है

भेदभाव; जहाँ भेदभाव राज्य की कार्रवाई का परिणाम है, वह

यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है: इसलिए, एक सिद्धांत का उल्लंघन

राज्य द्वारा प्राकृतिक न्याय की कार्रवाई अनुच्छेद का उल्लंघन है।

14. हालांकि, अनुच्छेद 14 इसका एकमात्र भंडार नहीं है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। यह क्या गारंटी देता है कि उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या राज्य की कार्रवाई को रोका जाएगा

केवल विधान और राज्य की कार्रवाई के लिए, लेकिन यह भी कि जहां कोई न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या पुरुषों का निकाय, जो इसके भीतर नहीं आता है

अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, के कर्तव्य के साथ आरोपित है

किसी विषय का निर्णय लेना। ऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

यह आवश्यक है कि उसे इस तरह के मामले को निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से तय करना चाहिए।

(जोर दिया

गया)

70. छावनी बोर्ड बनाम। तारामणि देवी 5 1, दो-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने माना कि ऑडी अल्टरम पार्टेम का नियम इसका एक हिस्सा है

अनुच्छेद 14. इसी तरह, दिल्ली परिवहन निगम बनाम। डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस 52, इस न्यायालय ने कहा कि ऑडी अल्टरम पार्टिम का नियम अनुच्छेद 14 में समानता खंड को लागू करता है। इसलिए, कोई भी प्रशासनिक कार्यवाई जो ऑडी अल्टरम पार्टिम के नियम का उल्लंघन करती है, मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन।

71. प्रशासनिक कार्यवाहियाँ जिनमें महत्वपूर्ण नागरिक कार्यवाहियाँ शामिल होती हैं

परिणामों को प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

51 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 501 52 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 600 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्याया। जहां संभव हो, ऑडी अल्टरम पार्टिम के नियम को एक वैधानिक नियम के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसे अनुच्छेद 14 के तहत परिकल्पित समानता और गैर-मनमानेपन के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं हैं

उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करें। ऑडी अल्टरम पार्टिम को तब धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए।

72. ओला टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम, ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ को वैधता का फैसला करने के लिए बुलाया गया था

बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 314। इस प्रावधान ने नगर आयुक्त को बिना किसी सूचना के, किसी भी वस्तु, संरचना या स्थिरता को हटाने में सक्षम बनाया, जिसे किसी भी सड़क में या उस पर स्थापित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने संविधान पीठ का फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित प्रावधान का यह सुनिश्चित करने के लिए अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जिस प्रक्रिया पर विचार किया गया है वह निष्पक्ष और उचित है। यह आगे आयोजित किया गया था:

44. [...] धारा 314 में जो प्रावधान है वह यह है कि आयुक्त, बिना किसी सूचना के अतिक्रमण हटा दें। करता है।

यह आदेश नहीं देता कि आयुक्त बिना किसी सूचना के कारण बताएगा हटाने के लिए एक अतिक्रमण। इसे अलग तरह से रखते हुए, खंड

314 आयुक्त को कारण बनाने का विवेकाधिकार प्रदान करता है

अतिक्रमण को सूचना के साथ या बिना सूचना के हटाया जाना। कि विवेक का प्रयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि

संवैधानिक आदेश का पालन करने के लिए कि

व्याख्या क्योंकि यह वैधता को बनाए रखने में मदद करता है कानून। धारा 314 को एक आदेश के रूप में पढ़ना जिसमें नहीं है

अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस जारी करें

कानून को अमान्य बना दें।

(जोर दिया

गया)

73. भारत संघ में v. Col.J एन. सिन्हा 54, दो-न्यायाधीशों की पीठ

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रावधान: 53 (1985) 3 एस. सी. सी. 545

54 (1970) 2 एससीसी 458 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. [.....] यह सच है कि यदि कोई वैधानिक प्रावधान पढ़ा जा सकता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, अदालतें

ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि विधायिकाएँ और वैधानिक प्राधिकरण कार्य करने का इरादा रखते हैं

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार। लेकिन अगर

दूसरी ओर एक वैधानिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या द्वारा

आवश्यक निहितार्थ किसी भी या सभी के अनुप्रयोग को बाहर करता है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तो अदालत जनादेश को नजरअंदाज नहीं कर सकती विधानमंडल या सांविधिक प्राधिकारी का और

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान। चाहे वह

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तदनुसार किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत पर निर्भर करता है या नहीं शक्ति, प्रकृति प्रदान करने वाले प्रावधान के व्यक्त शब्द

प्रदत्त शक्ति का, वह उद्देश्य जिसके लिए इसे प्रदान किया जाता है और

उस शक्ति के प्रयोग का प्रभाव।

(जोर दिया

गया)

74. सी बी गौतम बनाम। भारत संघ ", ए के सामने प्रश्न

इस न्यायालय की संविधान पीठ यह थी कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-C की धारा 269-यू. डी. (1) के तहत अनिवार्य खरीद करने से पहले संपत्ति के इच्छुक खरीदार और विक्रेता को कारणदर्शक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एम. एच. कनिया ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि जहां किसी प्रावधान की वैधता होगी सुनवाई के अवसर के अभाव में गंभीर चुनौती के लिए तैयार, न्यायालयों ने इस तरह की आवश्यकता को प्रावधान में पढ़ा है। सी बी गौतम (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों को अध्याय XX-C के प्रावधानों में पढ़ा ताकि उन्हें मनमानेपन के दोष से बचाया जा सके। द.

संविधान पीठ ने कहा:

30. [.....] पुनः, अध्याय XX-C में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

कारण दर्शाओ नोटिस या उचित अवसर देने पर रोक लगाना।

कारण दिखाना और न ही अध्याय की भाषा में कुछ है

XX-C जो इस तरह के निहितार्थ का कारण बन सकता है। इसका पालन

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की निष्पक्षता की व्यावहारिक आवश्यकता है।
कार्रवाई में खेलते हैं। हमारे विचार में, इसलिए, एक की आवश्यकता

आदेश से पहले कारण दिखाने का अवसर

केंद्र सरकार द्वारा खरीदी एक उपयुक्त द्वारा की जाती है

धारा 269 के तहत प्राधिकरण-यू. डी. को प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए।

55 (1993) 1 एससीसी 78 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अध्याय XX-C. खंड की भाषा में कुछ भी नहीं है

इस तरह के अवसर को नकारा जाएगा। इसके अलावा, यदि ऐसी आवश्यकता को प्रावधानों में नहीं पढ़ा गया था

उक्त अध्याय, वे गंभीरता से चुनौती के लिए खुले होंगे

अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर

प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर

न्याय। प्रावधान है कि जब खरीद के लिए आदेश दिया जाता है

धारा 269 के तहत-यू. डी.-कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए

उचित प्रावधान के लिए कोई विकल्प नहीं है
ऐसा आदेश दिए जाने से पहले सुनवाई का अवसर।

(जोर दिया गया)

75. सहारा इंडिया (फर्म) में, लखनऊ बनाम. के आयुक्त

आयकर, केंद्रीय-15, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या निर्धारिती के खातों की विशेष लेखा परीक्षा के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (2 ए) के तहत कोई निर्देश जारी करने से पहले किसी निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 142 (2-ए) के तहत शक्ति का प्रयोग गंभीर नागरिक परिणामों की ओर ले जाता है निर्धारिती को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को उक्त प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए।

76. केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 3 7, द

अदालत ने उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 633 (7) की वैधता को चुनौती दी, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शन जारी किए बिना बांड की शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की अनुमति दी गई थी।

कारण सूचना। न्यायाधीश डी. के. जैन ने दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि नियम 633 (7) के तहत आदेश दिए जाने से पहले एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए चुनौती देने के लिए खुला होगा जब तक कि इसमें कारण दिखाने के अवसर की आवश्यकता को नहीं पढ़ा जाता है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

के संबंध में पूर्व उल्लिखित कानूनी सिद्धांतों की कसौटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता, हम हैं

राय है कि प्रकृति, दायरे को ध्यान में रखते हुए और

56 (2008) 14 एससीसी 151 57 (2011) 13 एससीसी 733 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 633 के उप-नियम (7) के तहत निर्देश के परिणाम

मांग की जाए कि कारण बताएँ नोटिस जारी किया जाए और व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सुनने का अवसर।

[.....]

32. हमारे विचार में, इसलिए, यदि अवसर की आवश्यकता है कारण दिखाने के लिए उक्त नियम में नहीं पढ़ा जाता है, एक कार्रवाई

इसके तहत उल्लंघन के रूप में चुनौती देने के लिए खुला होगा

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 इस आधार पर कि

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति

प्रावधान मनमाना है।

(जोर दिया

गया)

77. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में यह स्पष्ट किया गया है कि

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ता के लिए महत्वपूर्ण नागरिक परिणाम सामने आते हैं। के बाद से मास्टर निर्देश

धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को सुनने का अवसर प्रदान नहीं करती है, ऑडी अल्टरम पार्टिम के नियम को उक्त निर्देशों के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें मनमानेपन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

78. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम तर्क को भी संबोधित करना चाहते हैं

उधारकर्ताओं का कहना है कि एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता को धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों में पढ़ा जाना चाहिए। उधारकर्ताओं ने जाह डेवलपर्स (ऊपर) पर भी भरोसा किया, जहां यह माना गया कि

ऋणकर्ता को 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित करने वाली समीक्षा समिति को एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा बनाया जाना चाहिए। हम उधारकर्ताओं के इस तर्क से सहमत हैं क्योंकि: (i) एक तर्कपूर्ण आदेश एक पीड़ित पक्ष को यह प्रदर्शित करने की अनुमति देता है कि जिन कारणों ने प्राधिकरण को पीड़ित पक्ष के हितों के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए राजी किया, वे बाहरी या विकृत हैं; और (ii) कारणों को दर्ज करने का दायित्व शक्तियों के मनमाने प्रयोग पर रोक के रूप में कार्य करता है। 58 दर्ज किए जाने के लिए आवश्यक कारण

58 क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान, (2010) 9 एस. सी. सी. 496 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम।

राजेश अग्रवाल और ओआरएस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

न्यायालय के निर्णय के समान पीठ पर नहीं रखा जाएगा। कारण संक्षिप्त हो सकते हैं लेकिन उन्हें विवेक के उचित उपयोग का संकेत देकर निष्पक्षता के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।

79. ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति के आलोक में, हमारा मानना है कि ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम को खंड 8.9 में पढ़ा जाना चाहिए। 4 और 8.9। 5 में से

धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, ऋणदाता बैंकों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करके उधारकर्ता को एक अवसर प्रदान करना चाहिए और उधारकर्ता को उचित भुगतान करने की अनुमति देनी चाहिए।

हमारे उपरोक्त तर्क के अनुसरण में, हम मानते हैं कि द्वारा निर्णय ऋणदाता बैंकों द्वारा उधारकर्ता खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। बैंक इस निर्णय के अनुसार नए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

80. अंत में, उधारकर्ताओं ने तर्क दिया है कि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित हैं क्योंकि वे एक

बैंक्स एसोसिएशन। हम उधारकर्ताओं के इस तर्क को इस तथ्य के आलोक में स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उधारकर्ता और तीसरे पक्ष। एक अलग पायदान पर खड़े हो क्योंकि: (i) ऋणकर्ता धोखाधड़ी के मुख्य अपराधी हैं, जबकि तीसरे पक्ष केवल सहायक हैं; और (ii) यह उधारकर्ता हैं जो महत्वपूर्ण नागरिक परिणामों का सामना करते हैं। खंड 8.12 के अधीन निर्दिष्ट। 1 और 8.12। 2 , जबकि तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को केवल भारतीय बैंक संघ को संदर्भित किया जाता है जो ऐसे सेवा प्रदाताओं की सावधानी सूची रखता है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण पिछले पैराग्राफ में चर्चा को देखते हुए हमारे निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. निष्कर्ष 81. निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की आवश्यकता नहीं है।

आई.

दर्ज और पंजीकृत;

किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप न केवल

ii.

जांच एजेंसियों को अपराध की सूचना देना, लेकिन उधारकर्ताओं के खिलाफ अन्य दंडात्मक और नागरिक परिणाम भी हैं; उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त तक पहुँच से रोकना।

iii.

खंड 8.12 के तहत 1 धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के लिए गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं;

खंड 8.12 के तहत ऐसा प्रतिबंध 1 मास्टर की

iv.

धोखाधड़ी पर निर्देश उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा ऋण के लिए अविश्वसनीय और अयोग्य होने के कारण काली सूची में डालने के समान है। इस न्यायालय ने लगातार कहा है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

ऑडी अल्टरम पार्टेम का अनुप्रयोग निहित रूप से नहीं किया जा सकता है।

वी.

धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत बाहर रखा गया। धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत विचार की गई समय सीमा के साथ-साथ अपनाई गई प्रक्रिया की प्रकृति को देखते हुए, यह

ऋणदाता बैंकों के लिए अपने खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करना उचित रूप से व्यावहारिक है;

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मांग करते हैं कि उधारकर्ता

vi.

एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, और उनके खाते को वर्गीकृत करने से पहले बैंकों/जेएलएफ द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए

धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए; और

चूँकि धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं हैं

vii.

इससे पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करते हुए, उन्हें मनमानेपन के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए निर्देशों के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए।

ए. एन. के. ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. बनाम राजेश अग्रवाल और ओआरएस 529 डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

परिणामस्वरूप, 10 दिसंबर 2020 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखा गया है। फैसलों

तेलंगाना का जी. एच. न्यायालय दिनांक 22 दिसंबर 2021 और 31

2021 , और गुजरात उच्च न्यायालय दिनांक 23 दिसंबर

सीकार्डिंग से अलग रखें। दीवानी अपीलों का निपटारा किया जाता है। (ग) 2022 की सं. 138 का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया गया है। वहाँ

बी.

लागत के बारे में आदेश दें।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों का निपटारा किया

गया।

महेंद्र यादव, एलसीआरए)